



हिन्दुस्तान

भरोसा नए हिन्दुस्तान का

ऋषभ पंत बोले,
कार दुर्घटना के
बाद मुझे पैर
गंवाने का डर था



शुक्रवार
2 फरवरी 2024, नई दिल्ली, नगर संस्करण

• पांच प्रदेश • 21 संस्करण



SEASON SPECIAL SALE

*A precious selection of shawls,
stoles and scarves at
wholesale prices*



#shawls #stoles #scarves #saris



ahujasons

SHAWLS | STOLES | SCARVES | SARIS

Karol Bagh | Khan Market | South Extn. Part II
DLF Mall of India, Noida | DLF Promenade, Vasant Kunj



www.ahujasons.com

NEW
LAUNCH

MOTHER
DAIRY

maa jaisi

पेश है Pure *Buffalo Milk's*

ताकत खूब, खुशियाँ भरपूर



प्रोटीन से
भरपूर



एक्स्ट्रा
गाढ़ा



स्वाद
मजेदार





हिन्दुस्तान

मरोसा नए हिन्दुस्तान का

गरीब, महिलाओं, युवा, किसानों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
-निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

शुक्रवार

2 फरवरी 2024, नई दिल्ली, नगर संस्करण

वर्ष 89, अंक 28, 18 पेज, मूल्य ₹ 5.00, हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ मूल्य ₹ 10.50 एवं एचटी एज के साथ मूल्य ₹ 6.75

● पांच प्रवेश ● 21 संस्करण

अंतरिम बजट 2024-25: वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकलुभावन घोषणाएं नहीं कीं, दस वर्षों की उपलब्धियां गिनाईं

खुद पर भरोसे का बजट

■ सौरभ शुक्ल

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। उनके बजट भाषण में केंद्र सरकार की योजनाओं पर भरोसे की झलक साफ दिखी। वित्तमंत्री ने कोई लोकलुभावन घोषणाएं तो नहीं कीं, लेकिन बीते 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख जरूर किया। साथ ही उन्होंने आगामी वर्षों में सुधारों को आगे बढ़ाने का रोडमैप पेश किया।

सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, सरकार जुलाई में अपने बजट में भारत को विकसित देश बनाने के लिए विस्तृत रूपरेखा पेश करेगी। उन्होंने बताया कि 'सुधार, प्रदर्शन और बदलाव' के सिद्धांत के आधार पर सरकार अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाएगी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों के साथ आम सहमति बनाएगी।

लंबी अवधि के विकास पर जोर : वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट में चुनिंदा क्षेत्रों को राहत देने का काम किया। इन एलानों से उनका जोर लंबी अवधि के विकास पर ही रहा है।

स्टार्टअप को कर छूट के संकेत: सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने का एलान किया। सोलर पैनल लगाने पर इंसेंटिव का प्रावधान होगा। मध्यम वर्ग को घर देने के अलावा स्टार्टअप पर भी टैक्स छूट मिलेगी, इस बात के भी संकेत बजट से मिलते हैं।

कर विवादों पर राहत का प्रस्ताव: वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर भले राहत नहीं दी, लेकिन 2009-10 तक के 25 हजार और वित्तवर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के 10 हजार की छोटी राशि की पुरानी कर मांग से जुड़े विवादों से आम लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया।

हर चुनौती दूर की : एक घंटे से कम समय के भाषण में सीतारमण ने 10 वर्षों में सरकार की उन उपलब्धियों को रखा, जिससे देश 'नाजुक अर्थव्यवस्था' की श्रेणी से निकलकर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। उन्होंने कहा, 2014 से पहले की हर चुनौती को आर्थिक प्रबंधन और बेहतर राजकाज से दूर किया जा चुका है।

अंतरिक्ष क्षेत्र का बजट दो हजार करोड़ रुपये बढ़ा



अंतरिक्ष क्षेत्र के बजट में दो हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अंतरिक्ष विभाग को 13,042.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में कुल 11,070.07 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए 10,087 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर परमाणु ऊर्जा विभाग के बजट में कटौती की गई है।

बिहार और झारखंड के विकास पर खास ध्यान



बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकार का फोकस हमेशा से गरीब, किसान, नारी और युवा पर रहा है। बजट भी उसी मुहिम को आगे बढ़ाने वाला है। उनके मुताबिक देश में अगले दौर के आर्थिक सुधार पूर्वी हिस्से से होकर गुजरेंगे। इनमें आर्थिक योजनाओं को लागू करने का काम किया जाएगा। उन्होंने खास तौर पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नाम लेते हुए इन राज्यों की तरफ खास ध्यान दिए जाने की बात कही।

पूँजीगत व्यय 11% बढ़ाने का प्रस्ताव: सीतारमण ने 2024-25 का लेखाजुमा पेश करते हुए बताया कि सरकार आर्थिक वृद्धि को और गति देने के लिए पूँजीगत व्यय 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव कर रही है। वहीं, चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित कर इसे जीडीपी का 5.8% कर दिया है। अगले वित्त वर्ष में यह 5.1% रहने का अनुमान है।

47.66

लाख करोड़ व्यय का बजट पेश किया गया

30.03

लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान

- सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 5.1 फीसदी पर लाने का लक्ष्य रखा
- जुलाई के बजट में विकसित देश के लिए विस्तृत रूपरेखा पेश करने का इरादा जताया

सरकार श्वेत पत्र लाएगी

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा, सरकार वर्ष 2014 से पहले की आर्थिक स्थिति के बारे में श्वेत पत्र लाएगी। इससे ये पता चल सकेगा कि वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। एक अधिकारी ने कहा कि इसे अगले सप्ताह संसद में रखा जा सकता है।

रक्षा बजट में बढ़ोतरी

अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि पिछले साल यह आवंटन 5.94 लाख करोड़ रुपये था। इसके साथ ही सरकार ने सैन्य क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की।

शेयर बाजार में मामूली गिरावट

शेयर बाजार उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में गिरावट के साथ बंद हुए। धरेलू बाजार अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद अस्थिर हो गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला संसेक्स 106.81 अंक यानी 0.15 प्रतिशत गिरकर 71,645.30 अंक पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का सूचकांक निचटरी 28.25 अंक यानी 0.13 प्रतिशत गिरकर 21,697.45 अंक पर आ गया।

अंतरिम बजट केवल रंग-बिरंगे शब्दों का मायाजाल था। बड़े-बड़े और खोखले दावे करना सरकार की आदत है। बजट में पिछले वर्ष का ब्योरा और आने वाले साल का खाका होता है, पर इस बजट में दोनों में से कुछ भी नहीं है।

मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

अंदर

दिल्ली-एनसीआर को रपतार पर जोरP03

युवा दमखम दिखा सकेंगेP06



गरीब

पीएम गरीब कल्याण अनु योजना के लिए अंतरिम बजट में 20.5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल के दौरान करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे।

युवा

तकनीकी क्षेत्र में शोध के लिए एक लाख करोड़ का फंड दिया जाएगा, इससे शोधकर्ताओं को 50 साल तक ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।

अन्नदाता

फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा। तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बनेगी।

नारी

आयुष्मान भारत योजना के दायरे में सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आएंगी। वहीं, केंद्र सरकार ने बजट में 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने का फैसला किया है।

प्रमुख पांच

1 आयकर दरों में बदलाव नहीं
वित्त मंत्री ने आयकर स्लेब में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं, धरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर दर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी की गई है।

2 सेहत पर जोर
मौजूदा अस्पताल आवसंरचना का इस्तेमाल कर सरकार अधिक मेडिकल कॉलेज खोलेगी। इस विषय पर अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

3 मुफ्त बिजली
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सोलर पैनल के जरिये एक करोड़ परिवारों को हर माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे सालाना हर परिवार के 18 हजार रुपये तक बचेंगे।

4 दो करोड़ घर
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पांच वर्षों में दो करोड़ घर बनाए जाएंगे। झुग्गी, अर्धकृत कॉलोनियों में रहने वालों को घर खरीदने में मदद के लिए योजना लाई जाएगी।

5 नए रेल गलियारे
तीन आर्थिक रेल गलियारे बनेंगे। इनमें ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट, बंदरगाह संपर्क और यातायात गलियारा शामिल हैं। 40 हजार बोगियां दूध भारत के तहत अपरोड की जाएंगी।

झारखंड में चंपई सोरेन आज सीएम पद की शपथ लेंगे

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड में चंपई सोरेन शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ दो और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार देर रात उन्हें सरकार बनाने का निर्माण दिया। उन्हें दस दिनों के भीतर बहुमत साबित करने को कहा गया है।

इससे पहले महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपई सोरेन के साथ पांच विधायकों ने गुरुवार शाम साढ़े पांच बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राजभवन के बाहर चंपई सोरेन ने पत्रकारों से कहा, उन्होंने राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। हेमंत सोरेन भी पब्लिक स्टेट में गिने जाएंगे। 'केंद्र सरकार तानाशाह': वहीं, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार बताया

सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

घनशोधन रोकथाम अधिनियम अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने घनशोधन मामले में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ का गठन किया।

और झारखंड की सरकार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के साथ मजबूती से होने की बात कही।

विधायक लोटे P11

केजरीवाल ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे

नई दिल्ली। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में ईडी के नोटिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को पूछताछ में शामिल नहीं होंगे।

आप ने अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो ईडी ने अभी तक पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है। पार्टी इस नोटिस को गैरकानूनी मानती है, इसलिए केजरीवाल पूछताछ में नहीं जाने का मन बना चुके हैं। उधर, शुक्रवार को आप का चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में प्रदर्शन है। केजरीवाल प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। यह भी बड़ी वजह है कि उनका शुक्रवार को पूछताछ में नहीं जाना लगभग तय है।

ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

नई दिल्ली/प्रयागराज, हिटी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के निचली अदालत के आदेश के विरोध में पूजा करने को लेकर मस्जिद कमेटी ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। दूसरी ओर, मंदिर पक्ष के शैलेंद्र पाठक ने केविपेट दाखिल कर उनका पक्ष भी सुनने की मांग की है।

इससे पूर्व ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन संभाल रही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शीर्ष अदालत में बुधवार रात दो बजे अर्जी दाखिल कर व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को राहत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता निजाम

- मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने की मांग की
- शीर्ष कोर्ट ने राहत देने से कर दिया था इनकार

पाशा और फुजैल अहमद अय्यूबी ने अर्जी में कहा, निचली अदालत के आदेश की आड़ में प्रशासन जल्दबाजी में है, जबकि कोर्ट ने प्रशासन को जरूरी इंतजाम करने के लिए एक सप्ताह का वक़्त दिया था। इससे पूर्व बुधवार रात साढ़े 10 बजे व्यास जी के तहखाने को खोला गया और पूजा की गई। व्यास परिवार के सदस्य जितेंद्र नाथ व्यास ने बताया कि पूजा लगभग 40 मिनट चली। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

पूजा शुरू P12

विश्वास | प्रधानमंत्री ने अंतरिम बजट को समावेशी और नवोन्मुखी बताया, युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी कहा

यह बजट भारत के मजबूत भविष्य की गारंटी: मोदी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट को समावेशी तथा नवोन्मुखी बताते हुए कहा कि यह 2047 के विकसित भारत की गारंटी है। उन्होंने कहा, इस बजट में निरंतरता का विश्वास है। यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को सशक्त करेगा। यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है।

अंतरिम बजट के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अनुसंधान एवं नवोन्मुखी पर एक लाख करोड़ रुपये का कोष बनाने की घोषणा की गई है। बजट में

स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का एलान भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखते हुए पूँजीगत व्यय को 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक ऊँचाई दी गई है।

अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो यह एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे 21वीं सदी के आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके मिलेंगे। आरामदायक होगा रेल सफर: मोदी ने कहा, बजट में वंदे भारत

स्टैंडर्ड की 40 हजार आधुनिक बोगियां बनाकर, उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का एलान किया गया है। इससे अलग-अलग रेल मार्गों पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। हर बार नया लक्ष्य तय करते हैं :

लक्ष्मीप में पर्यटन को रपतार देने की तैयारी सरकार लक्ष्मीप को बढ़े पैमाने पर पर्यटन के लिए विकसित करने की तैयारी में है। इसके लिए पोत संपर्क, पर्यटन के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने द्वीप समूह क्षेत्रों के विकास को कई प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की।

बजट में जिस आयकर माफ़ी योजना की घोषणा की गई है, उससे देशभर में मध्यम वर्ग के करीब एक करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछली सरकारों ने सामान्य लोगों के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। उन्होंने कहा, इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं।

किसानों, करदाताओं का जिक्र

विको
— विश्वस्तनीय आयुर्वेद —
१९९२ से

ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा

एक के साथ एक मुफ्त पाएं*

अब विको के दर्जेदार उत्पादों के साथ आयुर्वेद की खूबियों को घर लाएं और परिवार सहित स्वस्थता की दिशा में एक और कदम बढ़ाएं। आयुर्वेद के गुण अनेक, इसका लाभ उठाएं हर एक!

सोचें नहीं, आज ही खरीदें, यह ऑफर नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध है।

विको वचदंती सौफ्र पेस्ट

विको लोशन

विको एलो केयर क्रीम

विको नारायणी क्रीम

विको शेविंग क्रीम बेस

*खरीदें गए उत्पाद के साथ वही समान उत्पाद बिल्कुल मुफ्त पाएं।
*Products also available without offer *Available in select cities and stores

संपूर्ण स्वदेशी

Follow us on @vicolabs • Like us on [Facebook] Viccolabs
Shop online at https://viccolabs.com • Customer Care No. 0712-2420890

हमारी वेबसाइट पर ऑफर का लाभ उठाने के लिए QR कोड को स्कैन करें।



1.37

लाख करोड़ दूर संचार मंत्रालय को आवंटित

1.68

लाख करोड़ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को दिए

9,652

करोड़ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए



भले यह बजट अंतरिम है लेकिन इसमें बुनियादी ढांचे, सामाजिक क्षेत्र, कृषि और देश की अर्थव्यवस्था सहित हर क्षेत्र पर ध्यान स्पष्ट है।
- किरन रिजिजू, पृथ्वी विज्ञान मंत्री

मोदी सरकार की गारंटी

गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान

9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला



अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

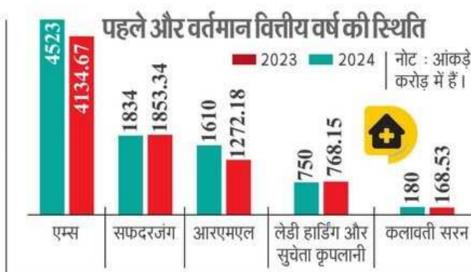
हमारा संकल्प विकसित भारत



केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में दिल्ली-एनसीआर की रफ्तार और सेहत सुधारने पर पूरा जोर दिया है। यही वजह है कि एनसीआर के शहरों के बीच विकास की योजना बनाने वाले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के लिए बजट में 55 करोड़ रुपये दिए गए हैं। नमो भारत ट्रेन को दिल्ली-मेरठ के बाद अन्य रूटों पर भी जल्द रफ्तार मिल सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र भी किया है। वहीं, एम्स समेत तीन बड़े अस्पतालों के बजट में सात सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है...

दिल्ली-एनसीआर की रफ्तार और सेहत सुधारने पर जोर

केंद्र के तीन अस्पतालों को 737 करोड़ रुपये मिले



परिवहन

3596

अच्छी कनेक्टिविटी के लिए नमो भारत का गुरुग्राम में रूट बदला जा रहा

अब अलवर रूट पर काम शुरू होना है



एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के लिए 55 करोड़ रुपये
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के लिए बजट में 55 करोड़ रुपये दिए गए हैं। गत वर्ष एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को 65 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, लेकिन संशोधित बजट में इसे घटाकर 55 करोड़ कर दिया गया। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन को 5.25 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया गया है।

नई दिल्ली, मुख्य संवाददाता। दिल्ली-मेरठ के बाद नमो भारत के दूसरे रूटों को भी रफ्तार मिलेगी। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका उल्लेख किया है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एनसीआरटीसी) को गत वर्ष की तरह इस बार भी 3596 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिल्ली-मेरठ रूट के बाद दिल्ली अलवर रूट पर काम शुरू होना है।
बजट भाषण में केंद्र सरकार ने दर्शाया है कि शहरों के बीच आसान सफर के ट्रेक को जल्द ही केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली-मेरठ रूट पर 17 किलोमीटर की दूरी में नमो भारत का संचालन हो रहा है। अगले वर्ष तक सरायकाले खां से मेरठ के बीच नमो भारत दौड़ने लगेगी। एनसीआरटीसी ने इसके साथ दिल्ली-अलवर रूट पर तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए गुरुग्राम में रूट बदला जा रहा है। एयरोसिटी के बाद नमो भारत का संचालन यहाँ एनएच पर ही होगा। इस ट्रेक को जल्द ही केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

गाजियाबाद-जेवर परियोजना तेज होगी

यूटन नोएडा। अंतरिम बजट से गौतमबुद्ध नगर की मेट्रो, नमो भारत ट्रेन और जेवर से चोला, खुर्जा और पलवल तक ट्रेन लाइन परियोजना को गति मिलेगी। ग्रेनो वेस्ट मेट्रो, सेक्टर-142 मेट्रो रूट के लिए फंड का इंतजाम हो सकेगा। इसी तरह गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन में फंड की कमी आने नहीं आएगी। नमो भारत ट्रेन गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक 72.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर चलेगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार करेगी।

साहिबाबाद मेट्रो रूट की उम्मीद जगी

गाजियाबाद। बजट में मेट्रो विस्तार को गति देने के एलान के बाद साहिबाबाद से नोएडा सेक्टर-62 तक मेट्रो रूट की उम्मीद भी जगी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) इस योजना पर लंबे समय से काम कर रहा है। जीडीए मेट्रो की रेड और ब्लू लाइन को जोड़ने में जुटा है। इसे लेकर प्राधिकरण ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से संशोधित डीपीआर तैयार कराई है। जीडीए ने संशोधित डीपीआर शासन को भेज दी है। अब शासन स्तर से इस संशोधित डीपीआर को अंमल में लाया जाएगा।

दिल्ली-अलवर के बीच रेल ट्रेक बनेगा

नई दिल्ली। राजधानी में रेलवे से संबंधित विकास कार्यों और सुरक्षा के लिए केंद्र ने बजट में 2577 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा है कि यूपीए-2 सरकार के समय में दिल्ली रेलवे को मिलने वाली राशि का यह 25 गुना से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली डिवीजन को मिले बजट से दिल्ली से अलवर के बीच 104 किलोमीटर का नया ट्रेक बनाया जाएगा। नई दिल्ली से तिलक ब्रिज के बीच 5वीं और छठी लाइन बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई 2.65 किलोमीटर है।

स्वास्थ्य

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली में एम्स समेत केंद्र के तीन अस्पतालों के बजट में कुल 737.62 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इनमें एम्स, आरएमएल और बच्चों के अस्पताल कलावती सरन का वित्तीय बजट बढ़ा है, जबकि सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े सुचेता कृपलानी अस्पताल के बजट में मामूली कटौती की गई है।



एम्स को 388 करोड़ रुपये मिले: एम्स दिल्ली के बजट में कुल 388.33 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एम्स का बजट 4134.68 करोड़ रुपये था, जिसे इस वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 4523 करोड़ किया गया है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) के बजट में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है।
आरएमएल का बजट 337.82 करोड़ रुपये बढ़ा है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के 1272.18 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1610 करोड़ रुपये हो गया है। बच्चों के कलावती सरन अस्पताल

इन्हें थोड़ा कम मिला

सफदरजंग अस्पताल के बजट में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 19.34 करोड़ रुपये की कटौती हुई है। यह पहले के 1853.34 करोड़ के मुकाबले घटकर 1834 करोड़ रुपये रह गया है। लेडी हार्डिंग और सुचेता कृपलानी अस्पताल का बजट 18.15 करोड़ रुपये घटा है। पहले के 768.15 करोड़ रुपये के मुकाबले 750 करोड़ रुपये तय किया गया है।
का बजट 11.47 करोड़ रुपये बढ़ा है। पहले यह 168.53 था, जो अब 180 करोड़ रुपये हो गया है।

विशेषज्ञ की राय

डॉ. अश्विनी डालमिया, अध्यक्ष, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन



स्वास्थ्य समाधान पर और अधिक ध्यान की जरूरत

मोटे तौर पर यह बजट सकारात्मक है। गर्भाशय के कैंसर के टीके लगाना कदम स्वागत योग्य है, लेकिन इस तरह अन्य बीमारियों के वैक्सिन को आवश्यकता, बचाव से जुड़े स्वास्थ्य समाधान पर और जोर देने की जरूरत है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर इलाज के लिए बजट में कुछ प्रावधान होना चाहिए था। बजट में मात्र 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र अभी भी किसी

सरकार की प्राथमिकता नहीं है। अमेरिका का स्वास्थ्य बजट कुल घरेलू सकल उत्पाद का 19 प्रतिशत है, जबकि हमारे देश में यह आंकड़ा मात्र दो प्रतिशत से भी कम है।
कोरोना महामारी ने गांवों और शहरी इलाकों के साथ-साथ सरकारी और निजी हेल्थकेयर सिस्टम में क्वालिटी के बड़े फर्क को उजागर किया था। इसलिए सरकारी हेल्थकेयर सिस्टम में बड़े बदलाव करने चाहिए।

आरएमएल के मेडिकल कॉलेज को गति मिलेगी

नई दिल्ली (प्र.सं)। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के बजट में बढ़ोतरी से अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय शुक्ला ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस साल बजट में बढ़ोतरी से मेडिकल कॉलेज की नई इमारत और सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण पूरा होगा।

विशेष सुविधाएं होंगी
अस्पताल के नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण अप्रैल तक होना है। 1500 बिस्तरों के इस ब्लॉक में कैंसर रोगियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, यहां दंत, किडनी, यूरो और न्यूरो के इलाज की भी बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

रोजगार की बात नहीं : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्र.सं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्द सिंह लवली ने बजट को बेहद निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के भविष्य के लिए यह अंतिम बजट साबित होगा। बजट में रोजगार देने के लिए एक शब्द तक नहीं होना भाजपा सरकार की विफलता को दर्शाता है।

DHIRSONS JEWELLERS PVT LTD
— DHIRAJ DHIR GROUP —
Today's Hallmark **92% Gold Rate**
₹58600/- per 10gms.
.916 certified by B.I.S.
MAKING CHARGES ONLY 7% ON ALL ITEMS
LAJPAT NAGAR-II: D-32, Central Market New Delhi - 110024. Ph: 47284728

इग्नू, केवीएस-एसपीए की धनराशि में इजाफा

शिक्षा

डीयू के कुलपति बोले, उत्साह बढ़ाने वाला बजट

नई दिल्ली, प्र.सं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) और केंद्रीय विद्यालय संसद (केवीएस) का बजट बढ़ा दिया गया है।
इग्नू का बजट जो सत्र 2023-24 में 130.80 करोड़ था, वह अब 2024-25 में 140 करोड़ हो गया है। एसपीए का बजट 2023-24 में 178 था, जो 2024-25 में 185.85 करोड़ दिया गया है। केवीएस की राशि में 802 करोड़ का इजाफा किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवीएस को 8500 करोड़ रुपये

मिले थे, जिसे बढ़ाकर 9307.67 करोड़ किया गया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इग्नू के कुलपति प्रो. नागेश्वर राव का कहना है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ा है। इग्नू सस्ती शिक्षा, उपयोगी पाठ्यक्रम और छात्रों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोर्स संचालित करता है। नए पाठ्यक्रम खोल भी रहे हैं। सरकार ने कार्यों की समीक्षा करने के बाद ही वह निर्णय लिया है। डीयू के कुलपति और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक प्रो. योगेश सिंह का कहना है कि अभी यह अंतरिम बजट है, जो उत्साह बढ़ाने वाला है।

दिल्ली पुलिस का किराए के भवनों से पीछा छूटेगा

सुरक्षा

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। केंद्रीय बजट 2024-25 में दिल्ली पुलिस को 11,397.98 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 534.34 करोड़ रुपये कम है। हालांकि, वर्तमान बजट में दिल्ली पुलिस को इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पिछले संशोधित बजट से ज्यादा धनराशि मिली है। इससे पुलिस को अपने भवन मिलेंगे और किराए के भवनों से उसका कहीं हद तक पीछा छूट जाएगा। बजट 23-24 में दिल्ली पुलिस को इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 270 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन इसे संशोधित कर 188.50

पिछले साल इतना मिला

दिल्ली पुलिस के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 11932.03 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वित्त वर्ष 2024-25 में इसे कम कर 11397.98 कर दिया गया है। ऐसे में इस वित्त वर्ष में 534.34 करोड़ रुपए कम दिए गए हैं।
कर दिया गया था। नए वित्तीय वर्ष के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट को बढ़ाकर 220.48 करोड़ रुपये कर दिया गया है। दिल्ली के कई थाने अभी भी या तो किराए के भवनों में चल रहे हैं या सरकारी भूमि पर टोन शेड में चल रहे हैं। सभी पुलिसकर्मियों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

दावा | वित्त मंत्री आतिशी ने कहा- स्थानीय निकायों के लिए एक भी रुपया आवंटित नहीं हुआ, केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप

राजधानी का बजट जस का तस, आम आदमी पार्टी भड़की

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। केंद्रीय बजट में दिल्ली सरकार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अलग-अलग मद में कुल 1168 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट की तुलना में इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और वह जस का तस है। सिर्फ प्लांट में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली सरकार की मांग के बाद भी केंद्रीय करों में भागीदारी फिर नहीं बढ़ाई गई है। एमसीडी के लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

पहले और अब किस मद में कितनी धनराशि मिली

मद	2023-24	2024-25
सिख दंगा पीड़ितों	2	2
केंद्रीय करों में हिस्सा	--	--
आपदा बचाव फंड	15	15
केंद्रीय सहायता	951	951
अतिरिक्त सहायता	200	200.01
कुल	1168	1168.01

नोट : धनराशि करोड़ रुपये में है।

सहायता के रूप में आवंटित किया गया है। इसके अलावा आपदा बचाव फंड के रूप में बीते साल की तरह 15 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सिख दंगा पीड़ितों के लिए दो करोड़ रुपये और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना के लिए 200 करोड़ रुपये मिले हैं। दिल्ली सरकार को केंद्रीय बजट में कोई आवंटन नहीं किया गया है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने फिर दिल्ली के साथ सौतेले व्यवहार की परंपरा जारी रखी है। अगर दिल्ली को उसके अधिकार के तहत केंद्रीय

रोजगार को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार के केंद्रीय बजट ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। वर्ष 2014 में भाजपा ने कहा था कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अबकी बार मोदी सरकार। तब हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, आज दस साल हो गए कहां हैं वो नौकरियां। क्या दस साल में 20

करोड़ लोगों को नौकरियां मिली हैं। बहुत बड़ी बात हो होगी, अगर एक करोड़ नौकरियां भी दे पाएं। निजी क्षेत्र में नौकरियों को छोड़ें, केंद्र सरकार में दस लाख पद खाली हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं। आज फिर केंद्रीय बजट में 55 लाख नौकरी देने की घोषणा की गई है। आतिशी ने कहा कि बजट में महंगाई से लड़ने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है।

देशभर की स्थानीय निकायों के लिए अलग से प्रावधान किया है, लेकिन दिल्ली की एमसीडी के लिए एक रुपये का प्रावधान नहीं किया है। यह दिल्ली के प्रति सौतेला व्यवहार है। उन्होंने कहा कि फिर भी हम दिल्ली वालों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

डॉ. डार्वर
सस्सों आँवला
केश तेल

सस्सों और आँवला का पोषण, बिना विपत्तिपाहट

साधारण सस्सों के मुकाबले कम विपत्तिपा, बाल बनें रहें लंबे, मजबूत और खूबसूरत

100 ml अब सिर्फ ₹30/- में।
Ingredient benefits basis published scientific literature



छह वर्षों में पेश बजट के दौरान संसेक्स में पहली बार गिरावट बाजार में तेज हलचल के बीच निवेशक सतर्क रहे

उठा-पटक

मुंबई, एजेंसी। लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए अंतरिम बजट को लेकर घरेलू शेयर बाजार दम साधे रहे। लोकलुभावन वादों की बजाय विकास के लिए उठाए गए ठोस कदमों से शेयर बाजार में गुरुवार को पूरे दिन काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। संसेक्स और निफ्टी में सुबह के कारोबार में तेज शुरुआत हुई लेकिन दोपहर बाद इनमें गिरावट आई और अंत में गिरकर बंद हुए।

संसेक्स पिछले छह वर्षों में बजट पेश किए जाने के दिन चार बार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ लेकिन इस बार इसमें गिरावट दर्ज की गई। बजट भाषण से पहले संसेक्स के शुरुआती कारोबार में 248.4 अंकों की बढ़त रही। इसी तरह निफ्टी भी 62.65 अंक की बढ़त के साथ खुला।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया तो बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और



क्या कहते हैं विशेषज्ञ

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिम बजट में उम्मीद से कम ढांचागत व्यय से घरेलू बाजार थोड़ा निराश हुआ। बजट पेश किए जाने के दौरान सूचकांकों ने अपनी सारी बढ़त गंवा दी और अंत में गिरावट के साथ बंद हुए। अमूमन अंतरिम बजट को लेकर बाजार ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और इस बार भी यह सिलसिला कायम रहा।

2019 में रही थी तेजी

इससे पहले वर्ष 2019 में भी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। उसमें कई लोकलुभावन घोषणाएं की गई थीं, जिससे शेयर बाजार में तेजी का रुख बना था। संसेक्स में कारोबार के दौरान 500 अंकों तक का उछाल आया। बाद में यह 213 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ था।

संसेक्स 72,151.02 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। लेकिन, जैसे ही उनका भाषण समाप्त की ओर बढ़ा बाजार में गिरावट आने लगी। अंत

इनमें उतार-चढ़ाव

संसेक्स की कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, बजाज फाइनेंस, विप्रो, टेक महिंद्रा और नेस्ले में प्रमुख रूप से गिरावट रही। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी और इंडसइंड बैंक के शेयर लाभ में रहे।

में संसेक्स 106.81 अंक गिरकर 71,645.30 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 28.25 अंक गिरकर 21,697.45 अंक पर आ गया।

विनिवेश से 50 हजार करोड़ जुटाए जाएंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट में विनिवेश के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल का बजट पेश करते के समय वित्त वर्ष 2023-24 में विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था।

चालू वित्त वर्ष में अभी तक सरकार ने कोल इंडिया, एनएचपीसी और आईआरडीडीए सहित सात सरकारी उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 12,504 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सरकार को मार्च 2024 तक विनिवेश से कुल 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।

देशभर में नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट में ईवी क्षेत्र (इलेक्ट्रिक वाहन) के लिए भी कई प्रस्ताव पेश किए। उन्होंने कहा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार चार्जिंग स्टेशन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी।

इस चार्जिंग निर्माण के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए उन्हें तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को ईवी चार्जिंग सेक्टर में रोजगार देने के लिए पर्याप्त मौके दिए जाएंगे। वहीं, सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 1,300 करोड़ रुपये और देश में विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए 24,931 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

फेम योजना के आवंटन में कटौती : सरकार ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम) की योजना के मद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,671 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। यह राशि संशोधित अनुमान से करीब 44% कम है।

प्रतिक्रियाएं

अंतरिम बजट 2047 तक देश के विकसित



भारत बनने के विश्वास को बढ़ाता है। देश सात प्रतिशत से अधिक की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छे संकेत हैं।

-एन. के सिंह, पूर्व अध्यक्ष, वित्त आयोग

अंतरिम बजट में किसी भी लोकलुभावन कदम



की घोषणा नहीं की गई, जैसा कि चुनाव पूर्व बजट में उम्मीद की जाती है। यह

आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसका स्वागत है।

-आनंद महिंद्रा, चेयरमैन, महिंद्रा समूह

निरंतर आर्थिक वृद्धि के लिए एक व्यापक



मार्ग प्रशस्त किया है, जो भारत को 2047 तक विकसित

अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने में सक्षम बनाएगा। -किरण मजूमदार शॉ, चेयरपर्सन, बायोकोन लिमिटेड

बजट में मध्यम वर्ग के लिए हाउसिंग स्कीम



और ग्रामीण गरीबों के लिए दो करोड़ और मकान बनाने की घोषणा हुई है। इन दोनों

ऐलानों से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलेगा।

-राकेश यादव, सीएमडी, अंतरिक्ष इंडिया

निःसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी ईलाज

INDIRA IVF
FERTILITY & IVF CENTRE

मातृत्व एक सुखद अहसास IVF से जगी नयी आस अधिक उम्र में माँ बनना हो रहा है संभव

आधुनिक तकनीकों जैसे आईवीएफ द्वारा अब 40 या उससे अधिक उम्र एवं मासिक धर्म बंद होने पर भी डोनर सर्विसेज के माध्यम से माँ बनना संभव हो पा रहा है।



निःशुल्क परामर्श

8867731100

परामर्श हेतु कौन दम्पति सम्पर्क कर सकते हैं?

- कम शुक्राणु • निल शुक्राणु
- धीमी गतिशीलता • खराब गुणवत्ता
- बंद फेलोपियन ट्यूब • अण्डों में खराबी
- गर्भाशय में रसोली/PCOS • अनियमित पिरियड
- एंडिनोमायोसिस • एन्डोमेट्रियोसिस

उपलब्ध सेवा - फर्टिलिटी जाँच • IUI • IVF • ICSI • लेज़र हैचिंग • ब्लास्टोसिस्ट • हिस्ट्रोस्कोपी • लेप्रोस्कोपी • डोनर सर्विसेज

इन्दिरा आई.वी.एफ. हॉस्पिटल प्रा. लि.

दिल्ली (पटेल नगर) : 1/14, मेट्रो पिलर नंबर 199 के सामने, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली। दिल्ली (लाजपत नगर) : ब्लॉक बी/24, मेट्रो पिलर नं. -9 के सामने, बंधन बैंक के पास, लाजपत नगर, नई दिल्ली। दिल्ली (रोहिणी) - D-11/145, , रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, पिलर नं. 391 के सामने, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली। दिल्ली (द्वारका) : विवा शोरूम के ऊपर, पालम एक्सप्रेसवे, रामपाल चौक, ब्रह्मा अपार्टमेंट्स के पास, सेक्टर-7, द्वारका। दिल्ली (तिलक नगर) : मेट्रो पिलर नं. 502 के सामने, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास, Axis बैंक के पीछे, तिलकनगर, नई दिल्ली। दिल्ली (शाहदरा) : विशाल मेगा मार्ट के सामने छत्रपुर, दुर्गापुरी चौक के पास, शाहदरा, दिल्ली। दिल्ली (वसंतकुंज) : एलआईसी आफिस के ऊपर, सेक्टर-बी1, दिल्ली जल बोर्ड के पास, वसंतकुंज, नई दिल्ली। कोशास्त्री (गाजियाबाद) : विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स, मेट्रो पिलर नं. 191 के पास, यूनियन बैंक के ऊपर, सेक्टर-14, कोशास्त्री, गाजियाबाद। राजनगर (गाजियाबाद) : C-29, RDC, ICICI बैंक के सामने, राजनगर, गाजियाबाद। गुरुग्राम : पिच्चा हट के पास, सेक्टर-14 कॉमर्शियल मार्केट, पुरानी दिल्ली रोड, गुरुग्राम। नोएडा (सेक्टर-18) : बैंक ऑफ बड़ोदा के ऊपर, गरम-धरम ढाबा के आगे, नोएडा कॉम्प्लेक्स नं. 17, सेक्टर-18, नोएडा। नोएडा (सेक्टर-34) : इंदिरा आईवीएफ रवि वुमन्स हॉस्पिटल, गोलफ कोर्स रोड, मेट्रो पिलर 200 के सामने, मोरना बस स्टैंड के पास, नोएडा (निकटतम मेट्रो स्टेशन सेक्टर-34) अपोइन्टमेंट हेतु कॉल करें-8585808073

- 120+ Fertility Centres PAN India
- Treatment protocol as per patients need
- Experienced team of 250+ Fertility Doctors

*येती बचाओ-बेटे बचाओ अभियान में सहयोग करें। भ्रूण सिंग परीक्षण करवाना जरूरी अरण्य है यह कार्य हमारे यहां मुफ्त किया जाता है।
Disclaimer : The models used in the creative is just for illustration purpose only.
*National Guidelines for Accreditation, Supervision & Regulation of ART Clinics in India compliant Clinic

TECNO

SPARK 20 Series THE UNCOMPROMISED

सेगमेंट फर्स्ट*

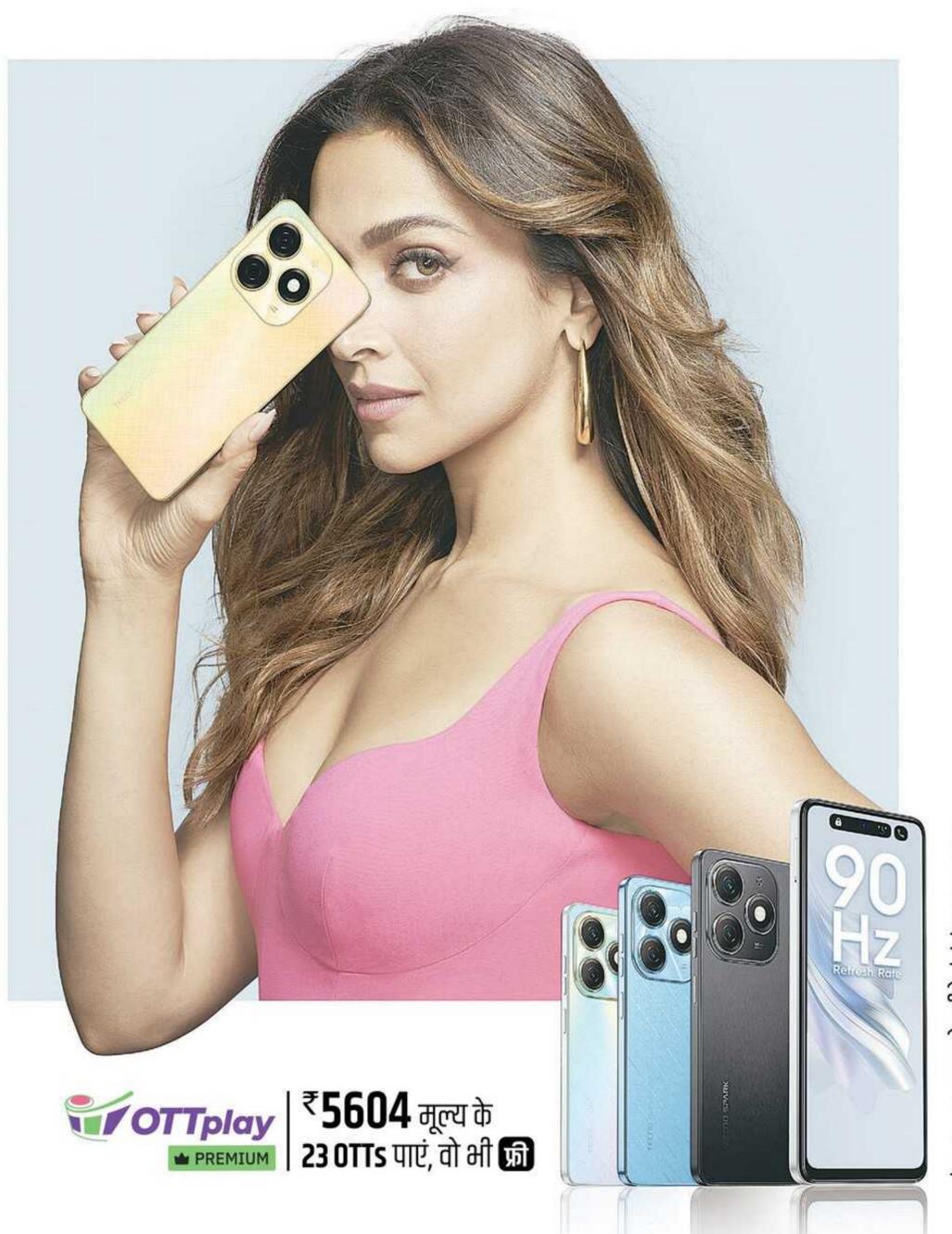
16GB** RAM | 256GB ROM

32MP सेल्फी कैमरा

₹9499.00# | Net Quantity - 1 N
से शुरू #Inclusive of All Taxes

नज़दीकी मोबाइल विक्रेता एवं amazon

पर उपलब्ध



OTTplay
PREMIUM

₹5604 मूल्य के
23 OTTs पाएं, वो भी फ्री



*₹10,499 मूल्य के नीचे | **8GB + 8GB



अधिक जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन करें | ₹1000 के कैशबैक के साथ pine labs और paytm पर उपलब्ध | सभी प्रमुख बैंकों के क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड पर लागू।

स्वास्थ्य • शिक्षा • युवा

38,183 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आवंटित किए 37,500 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा योजना के लिए दिए गए 13,208 करोड़ अनुसंधान और विकास पर खर्च होंगे

एक लाख करोड़ का कोष बनाना बाजी पलटने वाली नीति साबित होगी। यह कोष भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। - धर्मप्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री

अंतरिम बजट 2024-25

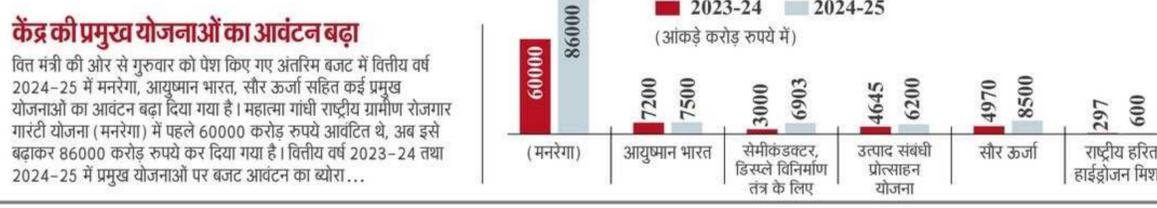


पहल: सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देगी, एक लाख करोड़ रुपये का कोष बनेगा, लंबी अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान से बदलेगी तस्वीर

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में तकनीक के क्षेत्र का स्वर्णिम युग शुरू होगा। सरकार तकनीक से जुड़े स्टार्टअप को अनुसंधान और नवाचार के लिए एक लाख करोड़ रुपये मुहैया कराएगी। ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बजट भाषण में यह घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने कहा, उभरते हुए क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान प्रयासों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक लाख करोड़ का कोष बनेगा। इसमें 50 वर्ष का ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा। इससे निजी क्षेत्र को रिसर्च और इन्वेंशन पहल करने को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं जो हमारे युवाओं की शक्ति को प्रौद्योगिकी से मिला सकें। भारत के प्रौद्योगिकी पसंद करने वाले युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम युग है। 'जय अनुसंधान': निर्मला सीतारमण ने लालबहादुर शास्त्री के दिए गए नारे जय जवान, जय किसान को दोहराया। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान' का नारा दिया है। डीप टेक से 'आत्मनिर्भरता': वित्त मंत्री ने डीप टेक तकनीकों पर भी चर्चा की। इसके तहत रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के लिए डीप टेक तकनीकों पर काम किया जाएगा। बता दें कि डीप टेक को एडवेंस तकनीक भी कहा जाता है। डीप टेक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।



स्टार्टअप को ये राहत भी... स्टार्टअप द्वारा किए गए निवेश पर कर प्रोत्साहन को मार्च, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ और साथ ही कुछ आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रही है। कराधान में निरंतरता प्रदान करने के लिए तारीख को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। स्टार्टअप इकाइयों स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्ययोजना के तहत आयकर लाभ जैसे कर प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती हैं।



बड़े अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। अंतरिम बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैसे तो कई नए कदमों का ऐलान किया गया है लेकिन इसमें मौजूदा बड़े अस्पतालों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भविष्य में ज्यादा नौजवानों को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार होगा। नए मेडिकल कॉलेज: अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा अस्पतालों के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उनमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एक समिति गठित होगी जो इन संभावनाओं का पता लगाएगी। दरअसल, मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए तीन सौ बिलों के एक अस्पताल की जरूरत होती है। आज देश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कई ऐसे अस्पताल हैं लेकिन उनमें मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहे हैं। समिति ऐसे अस्पतालों की पहचान कर उनमें मेडिकल कॉलेज खोलने की संभावनाओं का पता लगाएगी। बता दें कि देश में सात सौ मेडिकल कॉलेज पहले से हैं जिनमें एक लाख पांच हजार सीटें हैं। लेकिन देश की बढ़ती आबादी के कारण अभी भी मेडिकल कॉलेजों की कमी महसूस की जा रही है।

आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत के दायरे में लाना और किशोरियों के लिए टीकाकरण की पहल महत्वपूर्ण है। - भावना मुखोपाध्याय, कार्यकारी निदेशक, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया

लक्षद्वीप में पोत संपर्क बढ़ाकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार पर विशेष ध्यान पर्यटन को रफ्तार दी जाएगी

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार लक्षद्वीप को बड़े पैमाने पर पर्यटन के लिए विकसित करने की तैयारी में है। इसके लिए लक्षद्वीप से पोत संपर्क, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने द्वीप समूह क्षेत्रों के लिए कई घोषणा कीं। इस दौरान वित्त वर्ष 2024-25 में पर्यटन क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 2,449.62 करोड़ रुपये कर दिया, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े से लगभग 44.7 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2023 में

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार पर विशेष ध्यान... नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। शिक्षा क्षेत्र पर अंतरिम बजट में भी केंद्र सरकार ने अपना फोकस बरकरार रखा है। एक तरफ बुनियादी शिक्षा पर जोर है, वहीं उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार पर सरकार का ध्यान है। स्कूल शिक्षा के बजट में केंद्रीय योजनाओं के लिए करीब 19 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। जबकि स्कूल शिक्षा का कुल बजट भी पिछली साल की तुलना में बढ़ा है। उच्च शिक्षा का बजट आवंटन भी बढ़ाया गया है। केंद्रीय योजनाओं में ज्यादा खर्च: संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत केंद्रीय योजनाओं के लिए बजट आवंटन में 12,024 करोड़ रुपये यानी 19.56% की कुल वृद्धि हुई है। केवीएस और एनवीएस पर भी फोकस: केवीएस और एनवीएस के स्वायत्त निकायों में अब तक का सबसे अधिक बजट आवंटन देखा जा सकता है। केवीएस के लिये 9,302 करोड़ रुपए और नवोदय विद्यालय के लिये 5,800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। डिजिटल शिक्षा को ज्यादा पैसा: डिजिटल इंडिया लॉन्ग के तहत आवंटन में करीब 80 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। गत वर्ष 420 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 505 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अध्ययन को ज्यादा राशि: उच्च शिक्षा विभाग के तहत अध्ययन और नवाचार के लिए 355 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जबकि गत वर्ष यह आवंटन करीब 210 करोड़ रुपये था। सरकार ने इस वर्ष यूजीसी के बजट में 60 प्रतिशत की कटौती की है।

मनरेगा योजना को और मजबूती मिली सुविधाजनक और सुरक्षित रेल सफर

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री की ओर से गुरुवार को पेश अंतरिम बजट में मनरेगा योजना के लिए 86 हजार करोड़ का आवंटन किया गया। यह पिछले बजट में किये गए 60 हजार करोड़ रुपये के आवंटन से करीब 43 प्रतिशत अधिक है। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटन घट गया है। 2024-25 के अंतरिम बजट में इस योजना के लिए आवंटन 12 हजार करोड़ रुपये है जबकि पिछली बार यह 19 हजार करोड़ रुपये था। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए: वित्त मंत्री ने संसद में पेश अंतरिम बजट के दौरान कहा कि हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सीतारमण ने कहा कि इस समय सरकार की योजनाएं सीधे आम लोगों तक पहुंच रही हैं। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन के माध्यम से भोजन से जुड़ी चिंताओं को समाप्त कर दिया गया है। इसे पांच साल के लिए और बढ़ाया गया है और बजट में 2,05,250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है, इनमें से 23 लाख लोगों को पहली बार कर्ज मिला है। उन्होंने बताया कि जनधन खातों का भी लोगों को लाभ मिला है। 34 लाख करोड़ रुपये जनधन के जरिये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब या कम आय वाले लोगों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है।

जनकल्याण... नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री की ओर से गुरुवार को पेश अंतरिम बजट में मनरेगा योजना के लिए 86 हजार करोड़ का आवंटन किया गया। यह पिछले बजट में किये गए 60 हजार करोड़ रुपये के आवंटन से करीब 43 प्रतिशत अधिक है। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटन घट गया है। 2024-25 के अंतरिम बजट में इस योजना के लिए आवंटन 12 हजार करोड़ रुपये है जबकि पिछली बार यह 19 हजार करोड़ रुपये था। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए: वित्त मंत्री ने संसद में पेश अंतरिम बजट के दौरान कहा कि हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सीतारमण ने कहा कि इस समय सरकार की योजनाएं सीधे आम लोगों तक पहुंच रही हैं। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन के माध्यम से भोजन से जुड़ी चिंताओं को समाप्त कर दिया गया है। इसे पांच साल के लिए और बढ़ाया गया है और बजट में 2,05,250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है, इनमें से 23 लाख लोगों को पहली बार कर्ज मिला है। उन्होंने बताया कि जनधन खातों का भी लोगों को लाभ मिला है। 34 लाख करोड़ रुपये जनधन के जरिये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब या कम आय वाले लोगों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है।

गरीबों के अनुपात में गिरावट आई... 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मुद्रा योजना के तहत मंजूर किए गए इस वित्त वर्ष में... प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएई) कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में शुरू की गई थी। इसका मकसद, गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली दिक्कतों को दूर करना था। इस योजना के तहत नियमित तौर पर मासिक अनाज वितरित किया जाता है। हर व्यक्ति को हर महीने पांच किलोग्राम का अनाज मिलता है। बता दें कि इस योजना को नवंबर 2021 में चार महीने (दिसंबर 2021-मार्च 2022) के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद दोबारा से कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी, 2024 से पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था।

रेल यात्रा... नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में रेलवे के लिए कई घोषणाएं कीं। सरकार आम ट्रेनों की बोमियों को अपग्रेड कर वंदे भारत के स्तर की बनाने की तैयारी कर रही है। इस कदमों से आम लोगों को सुविधाजनक और सुरक्षित रेल सफर मुहैया कराने की योजना है। रेल के इतिहास में पहली बार 40,900 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश अंतरिम बजट में देश में तीन नए समर्पित रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। अमृत चतुर्भुज नामक कॉरिडोर देशवासियों को सेमी हाई स्पीड (160-240 किलोमीटर प्रतिघंटा) पर तेज-सुरक्षित रेल सफर मुहैया कराएगा। वहीं एनर्जी इकाओं के कॉरिडोर व रेल सागर कॉरिडोर टाइम टेबल से मालदुलाई की सुविधा प्रदान करेगा। अमृत चतुर्भुज: रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि अमृत चतुर्भुज में 16,900 किलोमीटर समर्पित सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, बंगलुरु आदि शहरों के बीच सेमी हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। सवा चार लाख करोड़ की लागत से 200 प्रोजेक्ट के तहत समूचा कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। अमृत चतुर्भुज पर वंदे भारत, अमृत भारत, स्लीपर वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को चलाया जाएगा।

रेल बजट में किस राज्य को कितना मिला... दिल्ली 2,577, उत्तर प्रदेश 19,575, बिहार 10,032, झारखंड 7,234, उत्तराखंड 5,120, हरियाणा 2,861

यात्रियों की संख्या... 623 करोड़ 2022-23, 344 करोड़ 2021-22

40,000 डिब्बों को अपग्रेड किया जाएगा... अंतरिम बजट में 40,000 डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदलने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो और नमो रेल का भी अन्य शहरों तक विस्तार किया जाएगा। शहरी रूपांतरण के लिए उत्तरेक मेट्रो रेल... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करने के दौरान कहा कि देश में तीव्र शहरीकरण हो रहा है और नमो भारत ट्रेन एवं मेट्रो रेल आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उत्तरेक बन सकती हैं। देश में रोज करीब एक करोड़ यात्री मेट्रो की सवारी कर रहे हैं। हवाई अड्डों के विस्तार और विकास पर जोर... वित्त मंत्री ने विमानन क्षेत्र के पिछले 10 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का निर्माण तेजी से जारी रहेगा। पिछले 10 वर्षों में देश के भीतर हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है।

महिला • किसान • रक्षा

70,163 करोड़ जल जीवन मिशन और पेयजल के लिए आवंटित

14,600 करोड़ रुपये फसल बीमा योजना के लिए दिए गए

6.21 लाख करोड़ रुपये रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किए

मोदी सरकार द्वारा किए गए अनेक उपाय निश्चित ही हमारे अन्नदाताओं का जीवन स्तर और ऊंचा उठाएंगे। अंतरिम बजट प्रगति का प्रतिबिंब है।

- अर्जुन मुंडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

अंतरिम बजट 2024-25



मजबूती : विकसित भारत के लिए तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, सुरक्षा पर भी ध्यान

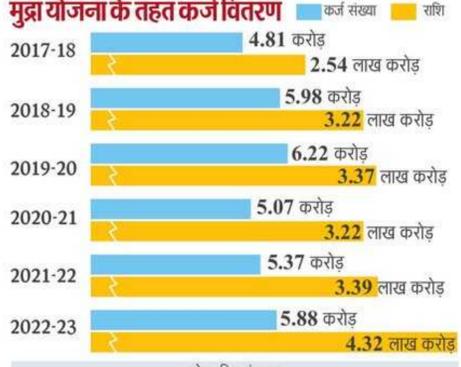
महिलाओं को सशक्त, समृद्ध बनाने पर जोर

आधी आबादी

09 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख समूह से बदलाव

30 करोड़ कर्ज मुद्रा योजना के तहत दिए गए

- लखपति दीदीयों को सम्मानित कर उपलब्धियों को मान्यता मिलेगी
- उच्च शिक्षा में महिलाओं की मागीदारी दस वर्षों में 28% तक बढ़ी
- मिशन वात्सल्य के लिए सरकार ने 1,472 करोड़ रुपये दिए



मुद्रा योजना श्रेणी

श्रेणी	कर्ज संख्या	राशि आवंटित	कर्ज राशि
शिशु	83	40	50 हजार रुपये तक
किशोर	15	36	50 हजार से 5 लाख
तरुण	02	24	05 लाख से 10 लाख

दिल्ली-चंडीगढ़ छोड़ सभी जगह चल रही योजना
लखपति दीदी योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 742 जिलों के 7091 ब्लॉक में चल रही है। 19.54 करोड़ महिलाओं को 87.39 लाख स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया गया है। चार लाख महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार प्रशिक्षित किया गया। 33,497.62 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।



केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करने के दौरान कोलकाता में गुरुवार को एक एसी आउटलेट में महिला कर्मचारियों को संबोधित किया।

बच्चों का भी ख्याल

बजट में महिलाओं के साथ बच्चों का भी ख्याल रखा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 2024-25 के लिए 26,000 करोड़ रुपये मिलें हैं। यह पिछले बजट की तुलना में 2.52 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 25,448.68 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में 21,200 करोड़ रुपये का सर्वाधिक आवंटन हुआ है।

40.82 करोड़ कर्ज वितरण के तहत मार्च 2023 तक 23.2 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए

68% कर्ज खाते योजना के तहत महिला एंटरप्रेन्योर से जुड़े हुए

महिला सशक्तीकरण ने दस वर्षों में रफ्तार पकड़ी

निर्मला सीतारमण ने कहा कि उद्यमिता और जीवनन्यापन की सुगमता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण में पिछले 10 वर्षों में तेजी आई है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महिलाओं के उत्थान के लिए हो रहे काम कार्यक्रमों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को बयान कर रहे हैं।

43% स्टैम कोर्स में लड़कियों-महिलाओं की भागीदारी, विश्व में सबसे ज्यादा

कामगार महिलाओं की भागीदारी बढ़ी 37.0%

मिशन शक्ति बजट में इजाफा बजट में मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन) को 3146 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। वर्ष 2023-24 में कुल बजट करीब 2326 करोड़ रुपये का था। महिला सुरक्षा से जुड़ी योजना में 955 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

30 करोड़ कर्ज मुद्रा योजना के तहत महिला एंटरप्रेन्योर को दिया गया

मालकिन बन रही महिलाएं वित्तमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 70 फीसदी घरों की चाबी महिलाओं को मिली है। योजना के तहत तीन करोड़ मकान बनाने के लक्ष्य के करीब हैं। अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त आवास बनाए जाएंगे।

देशभर में दो करोड़ लोगों को अपना आवास मिलेगा

मध्यम वर्ग

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में अपने भावी बजट की रूपरेखा के साथ विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकताएं भी तय की हैं। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में तीन करोड़ घर बनाए गए हैं और अगले 5 साल में दो करोड़ घर और बनाए जाएंगे।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए अंतरिम बजट में 1091.98 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मध्यम वर्ग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और तीव्र शहरीकरण हो रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उल्लेख बन सकते हैं। अंतरिम बजट में एमआरटीएम और मेट्रो परियोजनाओं के लिए पिछले बजट के 23175.01 करोड़ की तुलना में इस बार 24931.98 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

पीएम आवास योजना शहरी का बजट बढ़ा: वित्त मंत्री ने अपने भाषण में पीएम स्वनिधि का विशेष उल्लेख करते हुए कहा है कि इस योजना से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता प्रदान की गई है। इसमें 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने तीसरी बार ऋण प्राप्त किया है। हालांकि, अंतरिम बजट में इस मद में आवंटन कम किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष बजट आवंटन 468 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 326.32 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं।

आदिवासी न्याय महाभियान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी ने इस महान की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये

प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च

2023-24 79,590

2024-25 80,671

स्रोत: बजट (आंकड़े करोड़ रुपये में)

1,091 करोड़ अधिक और शहरी कार्य मंत्रालय को

26,170.61 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन का बजट घटा

स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आवंटन घटाया गया है। पिछली बार के 8000 करोड़ की तुलना में इस बार 2400 करोड़ का ही आवंटन किया गया है। अमृत मिशन के लिए इस बार भी पिछली बार की तरह 8000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने दो नई योजनाओं राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के लिए पहली बार 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी तरह से नव प्रवर्तन, एकीकरण और स्थायित्व के लिए शहरी निवेश 2.0 के लिए पहली बार 225 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महान अभियान (पीएम-जनमन) के तहत ग्रामीण आवास योजना के एक लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की थी।

विशेषज्ञ की राय

अनुज पुरी, चेयरमैन एनराक ग्रुप

बुनियादी ढांचे पर 11 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे

इंफ्रास्ट्रक्चर

नई दिल्ली, एजेसी। सरकार 2024-25 में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर रिकॉर्ड 11.11 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय का

तीन आर्थिक गलियारे

प्रधानमंत्री शक्ति के अंतर्गत पहचान किए गए तीन प्रमुख आर्थिक गलियारों का शुभारंभ किया जाएगा।

- ऊर्जा, खनिज-सीमेंट गलियारा
- पतन संपर्कता गलियारा
- भारी यातायात गलियारा

आवंटन चालू वित्त वर्ष के पूंजीगत व्यय से 11.1 फीसदी अधिक है। यह जीडीपी का 3.4% हो गया है।

शून्य उत्सर्जन के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा

हरित ऊर्जा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सौर पैनल (सौर इकाई) के जरिये एक करोड़ परिवारों को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। योजना से सालभर में 18 हजार रुपये की बचत होगी। सौर ऊर्जा उत्पादन से शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले छतों पर सौर ऊर्जा



300 यूनिट तक हर माह मुफ्त बिजली एक करोड़ परिवारों को

इकाई लगाने के लक्ष्य के साथ 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' शुरू किए जाने की घोषणा की थी। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटने के बाद एक करोड़ घरों में सौर पैनल लगाने की बात कही थी। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पर लिए गए प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करती है।

मुफ्त सौर बिजली के इस्तेमाल और बची हुई बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से सालाना 15 से 18 हजार रुपये तक की बचत होगी। योजना इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग में भी सहायता करेगी। इससे बड़ी संख्या में विक्रेताओं के लिए उद्यमशीलता के अवसर और तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

एक करोड़ घरों में सौर पैनल की घोषणा से सौर निर्माताओं को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। इससे भारत के हर कोने में सौर पैनल पहुंचेगा। -अश्वनी सहगल, एनडी और अख्यक, अत्येवक सोलर

सौर पैनल योजना ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ अक्षय ऊर्जा में उद्यमिता और रोजगार को भी प्रोत्साहित करेगी। -कुश सिंह, सीईओ, एस्सर पावर

अन्नदाता की आय बढ़ाने की कवायद

किसान

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकार तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बनाएगी। डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी शुरू होगा। गुरुवार को पेश अंतरिम बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कवायद की गई है।

12 करोड़ के करीब किसानों को आर्थिक मदद दी गई

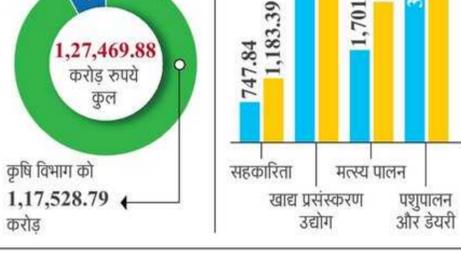
04 करोड़ किसानों को फसल बीमा मुहैया करा रही केंद्र सरकार

38 लाख किसान संपदा योजना से लाभान्वित नौकरियों भी पैदा हुई



अहमदाबाद में गुरुवार को धान रोपते किसान। • रॉयटर्स

कृषि मंत्रालय का बजट
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरडी) को 9,941.09 करोड़



तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए रणनीति बनेगी

सीतारमण ने कहा कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों पर काम होगा।

नैनो डीएपी का उल्लेख वित्त मंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो डीएपी (एक तरह का उर्वरक) के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा।

55 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य निर्मला सीतारमण ने अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना को बहाल करते हुए कहा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना ने 2013-14 से समुद्री खाद्य निर्यात को दोगुना करने में मदद की। 55 लाख नौकरियां पैदा करने को बढ़ावा दिया जाएगा।

आधुनिक तकनीक से लैस होगी सेना

रक्षा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकार ने गुरुवार को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। पिछले साल यह आवंटन 5.94 लाख करोड़ का इजाफा किया गया है। साथ ही सैन्य क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा भी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में पेश अंतरिम बजट में, पूंजीगत व्यय के लिए सेना को कुल 1.72 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान खरीदना शामिल है। पिछले साल यानी 2023-24 में पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.62 लाख करोड़ रुपये था। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में, भारतीय वायु सेना के लिए पूंजी परिव्यय सबसे अधिक 57,137.09 करोड़ रुपये था, जिसमें विमान और एयरो इंजन की खरीद के लिए 15,721 करोड़ रुपये और अन्य साजोसामान के लिए 36,223.13 करोड़ रुपये शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी डीप टैक से रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की बात कही गई है। सेना को कुल 1.72 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान खरीदना शामिल है। पिछले साल बजटीय आवंटन 1.62 लाख करोड़ रुपये था।

1.7 लाख करोड़ रुपये सेना के पूंजीगत व्यय के लिए दिया गया

5.9 लाख करोड़ रुपये पिछले साल रक्षा के लिए दिए गए थे

रक्षा बजट के तहत समग्र आवंटन से सेना के लिए सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। -डॉ. लक्ष्मण कुमार बेहरा, एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू

राजस्व व्यय में मंत्रालय के लिए 15,322 करोड़

एयरो इंजन के लिए 40,777 करोड़

सीबीआई को पिछले साल से कम मिला

सीबीआई को 928.46 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह वित्त वर्ष 2023-24 की अपेक्षा 40.4 करोड़ रुपये कम है। तब बजट अनुमान में 946.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट में संशोधित बजट अनुमान में बढ़ाकर 968.86 करोड़ कर दिया गया था।

राजस्व व्यय में मंत्रालय के लिए 15,322 करोड़

एयरो इंजन के लिए 40,777 करोड़

सीबीआई को पिछले साल से कम मिला

सीबीआई को 928.46 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह वित्त वर्ष 2023-24 की अपेक्षा 40.4 करोड़ रुपये कम है। तब बजट अनुमान में 946.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट में संशोधित बजट अनुमान में बढ़ाकर 968.86 करोड़ कर दिया गया था।

राजस्व व्यय में मंत्रालय के लिए 15,322 करोड़

एयरो इंजन के लिए 40,777 करोड़

सीबीआई को पिछले साल से कम मिला

सीबीआई को 928.46 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह वित्त वर्ष 2023-24 की अपेक्षा 40.4 करोड़ रुपये कम है। तब बजट अनुमान में 946.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट में संशोधित बजट अनुमान में बढ़ाकर 968.86 करोड़ कर दिया गया था।

सेनाओं के लिए कितना

थल सेना के लिए राजस्व व्यय 1,92,680 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि नौसेना और वायु सेना को क्रमशः 32,778 करोड़ रुपये और 46,223 करोड़ आवंटित किए हैं।

नौसेना बड़े के लिए 23,800 करोड़

नौसेना बड़े के लिए 23,800 करोड़ रुपये और नौसेना डॉकयार्ड परियोजनाओं के लिए 6,830 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विशेषज्ञ की राय

संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल

चुनौतियों पर ध्यान देना होगा

यह अंतरिम बजट है। पांच फीसदी बढ़ोतरी का मतलब है कि यह सिर्फ महंगाई की भरपाई की गई है। लेकिन हमें यह मानना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। जुलाई में जब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा तो उस समय वास्तविक जरूरत और चुनौतियों को ध्यान में रखकर बजट की जाएगी। एक बात और अंतरिम बजट के बावजूद सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए

1,72 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह पिछले बजट से दस हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। मौजूदा आधुनिकीकरण परियोजनाओं, नई खरीद आदि के लिए यह राशि कम नहीं है। इसके अलावा सेना के मामलों में सरकार पहले भी कह चुकी है कि जब जरूरत होगी तो बजट के अलावा भी अलग से उसे आवंटन किया जाएगा। मेरे विचार से अंतरिम बजट के हिसाब से अभी यह आवंटन पर्याप्त है।



विश्वास का प्रदर्शन

नरेंद्र मोदी सरकार के दसवें वर्ष का अंतिम व अंतरिम बजट पूरी तरह से आश्वस्त और भविष्योन्मुखी बजट है। यह कदापि चुनावी बजट नहीं है, क्योंकि दो महीने में देश में चुनाव होने जा रहे हैं, पर सरकार में किसी भी तरह की बेचैनी नहीं है। साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी वापसी के लिए आश्वस्त है। चूंकि यह अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती पर फोकस करता हुआ बजट है, इसलिए किसी भी प्रकार की नई तात्कालिक लोकलुभावन घोषणा से इसे बचाया गया है। लोकलुभावन घोषणा के रूप में केवल सूर्योदय योजना है, जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है, जिसके तहत देश के एक करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना है। ये ऐसे घर होंगे, जिनकी छतों पर सौर ऊर्जा के लिए संयंत्र स्थापित होंगे। न कॉर्पोरेट कर में कोई परिवर्तन हुआ है और न आयकर में किसी तरह की राहत दी गई है। अब वेतनभोगियों को चुनाव बाद आम बजट से ही उम्मीद रखनी चाहिए। बजट में नारी, युवा, किसान और गरीब पर विशेष नजर है और इसके सियासी मूल्य को सहज ही समझा जा सकता है। बहरहाल, संसद में अच्छे माहौल में बजट का पेश होना भी स्वागतयोग्य है।

इस अंतरिम बजट 2023-24 को हम 'गुड रिपोर्ट कार्ड बजट' भी कह सकते हैं, क्योंकि एक घंटे से भी कम समय के अपने बजट भाषण का अधिकतर हिस्सा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार की दस साल की उपलब्धियों की व्यवस्थित प्रस्तुति पर खर्च किया। चूंकि विकास दर संतोषजनक है, लगभग 7 प्रतिशत की विकास दर देश हासिल कर सकता है। सरकार का वित्तीय घाटा 5.9 के अनुमान से कम 5.8 रहा है और सरकार वित्त वर्ष 2025 में इसे 5.1 प्रतिशत करने के प्रति आश्वस्त है। कोई संदेह नहीं है कि यह सरकार के आत्मविश्वास से सराबोर बजट है। वित्तीय घाटे को एकदम से कम किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार को विकास की रफ्तार बनाए रखने के साथ

जनकल्याण के कार्यों-योजनाओं को भी चलाए रखना है। वाकई, देश का तेज विकास और जरूरतमंदों की मदद करना ज्यादा जरूरी है और वित्तीय घाटे की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार के समय में उच्च शिक्षा में महिलाओं का प्रवेश बढ़ा है और 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। लोगों की आय में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। साफ तौर पर केंद्र सरकार का फोकस आर्थिक न्याय पर है, अगर इसे सुनिश्चित किया जाए, तो सामाजिक न्याय में भी सहूलियत होगी।

नरेंद्र मोदी सरकार के समय में विदेशी पूंजी निवेश भी खूब आया है। करीब 596 अरब डॉलर का विदेशी पूंजी निवेश 2014 से 2023 के बीच आया है। हालांकि, यह अच्छी बात है कि सरकार को एहसास है, विदेशी पूंजी निवेश का पूरा लाभ देश को नहीं हुआ है, इसलिए सरकार एफडीआई की नई परिभाषा गढ़ रही है। 'फरिन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट' को अगर 'फर्स्ट डेवलप इंडिया' की ओर मोड़ दिया जाए, तो कमाल हो सकता है। सरकार ने युवाओं के कौशल विकास की दिशा में काफी काम किए हैं और अब लघु व मध्यम कंपनियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि उत्पादन के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि हो। कहने की बात नहीं कि बुनियादी ढांचे में सरकार का निवेश सराहनीय है और सरकार इसे जीडीपी का 3.4 प्रतिशत रखे हुए है। आगामी पूर्ण बजट में भी बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सरकार से ज्यादा बजट की उम्मीद रहेगी।

हिन्दुस्तान 75 साल पहले

31 जनवरी, 1949

अनाज के भावों में निरन्तर तेजी

हापड़, (डाक से)। इस सप्ताह प्रायः सब जिन्सों के भाव बढ़े हैं— क्या अनाज, क्या दाल, क्या गुड़ और क्या तिलहन। अनाजों में गेहूँ के भाव निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। हापड़ में अच्छे गेहूँ का भाव २९) हो गया है और प्रांत के कुछ नगरों में तो ३२) प्रति मन तक है। चने के भाव निसबतन कम हैं क्योंकि पंजाब तथा राजपूताने से कुछ अधिकृत रूप से और कुछ अनधिकृत रूप से चना आता रहता है। जौ, मक्का और बाजरे के भाव ऊंचे बने हुए हैं।

अनाज के भावों के बढ़ने के तीन प्रमुख कारण हैं, स्टोक की कमी, वर्षा न होने के कारण आने वाली फसल के बारे में चिन्ता और विशेषज्ञों के ऐलान हैं जो अनाज की कमी के अनुमान प्रति दिन बढ़ाते जा रहे हैं। अभी गत सप्ताह सरकारी हलकों का अनुमान था कि १९४९ में भारत को लगभग ४६ लाख टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन में हिन्दी प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री दिनेशर राव देसाई ने बतलाया है कि देश में लगभग ९० लाख टन अनाज की कमी है। आपने यह भी बताया है कि देश के पास इतना अनाज मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा के साधन नहीं हैं। इस स्थिति में क्या आश्चर्य है कि अनाज के दाम बढ़ने लगे और गेहूँ और चावल का तो बाजार में मिलना ही कठिन हो जाये। गेहूँ के वर्तमान भाव सरकार द्वारा नियत अपनी खरीद के भाव से दुगुने से भी ऊंचे हैं और चावल के भाव उन जिलों में जहां चावल और धान बहुतायत से पैदा नहीं होता कंट्रोल के भाव से करीब करीब दुगुने हैं। अन्य अनाज के भाव भी सरकारी भावों से बहुत ऊंचे हैं। यह है संयुक्त प्रांत की बातें। पूर्वी पंजाब में सरकारी हलकों के दावे के अनुसार जब से राशनियं प्रारम्भ हुआ है खाद्य स्थिति बहुत कुछ सुधर गई है। बताया गया है कि फिरोजपुर और लुधियाने जिले में गेहूँ का भाव गिरकर १८) प्रति मन हो गया है और मक्का और बाजय अब प्रायः सब जगह कंट्रोल रेट पर मिल जाते हैं।

खड़ी फसल की हालत अब तक संतोषजनक थी; लेकिन आगे सूखे से भारी नुकसान हो जाने का डर है; यदि बहुत शीघ्र वर्षा नहीं हो जाती है तो चाही इलाकों में फसल निश्चय रूप से हल्की रह जायेगी।

अब भ्रष्टाचारियों की नैया पार नहीं होगी

भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, जो यह मानते हैं कि सरकार उनकी है और वे कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की भ्रामक सोच भारतीय राजनीति का पतन कर रही है। इसकी शुरुआत और परतदर्शिता को धूमिल कर रही है। पहले राजनीति का अर्थ लोगों की सेवा करना होता था, लेकिन बाद में यह अपने लोगों की सेवा का माध्यम समझी जाने लगी। बिहार और झारखंड जैसे राज्य तो इसमें सबसे ऊपर दिखते हैं। झारखंड में ही अभी को उपायनक हुआ है, क्या उससे यह धारणा नहीं बनती कि हेमंत सोरेन ने जरूर कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि पहले उन्हें ईडी से 'भागना' पड़ा और जब उन पर दबिश बढ़ी, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर ईडी अधिकारियों के हाथों गिरफ्तार होना पड़ा।

पड़ोसी राज्य बिहार का हाल भी इससे

अलग नहीं है। वहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार खबरों में रहा है। उनके पुत्र तेजस्वी यादव व अन्य परिजन पर भी जमीन घोटाले के आरोप हैं। कहा जाता है कि जब ईडी ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे, तो वह भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने घोटाले के वक्त खुद के नाबालिग होने की बात कही। जब ईडी अधिकारियों ने पूछा कि करोड़ों की कंपनी कैसे बनाई, तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही। जबकि लालू यादव के पास इतनी संपत्ति कैसे जमा हुई, यह कोई छिपा रहस्य नहीं है। वह तो भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा तक खा चुके हैं, इसलिए यह कयास गलत नहीं है कि देर-सबेर तेजस्वी यादव भी अपने पिता की तरह जेल में दिख सकते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी देश के अन्य राज्यों में भी है, जहां मुख्यमंत्री और बड़े नेता

ईडी के निशाने पर हैं, इसलिए मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम और भी कई नेताओं को कालकोठी में देख सकते हैं।

इन सब घटनाओं का स्पष्ट मतलब है कि अब भ्रष्टाचारियों की नैया पार होने वाली नहीं है। अगर वे लोग सोचते हैं कि ताकतवर होने के कारण जानू उन तक नहीं पहुंच सकता, तो वे मुगालते में हैं। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी ही। भ्रष्टाचारण से करोड़ों-अरबों की संपत्ति लूटने वाले नेतागण शयद नहीं जानते कि केंद्र में ऐसी मनबूत सरकार है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ाश्चत नहीं करती। इसीलिए तो जांच एजेंसियों को पूरी छूट मिली हुई है कि वे भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ें। दुबक मुफ्त एजेंसियां अपने काम में जुटी भी हुई हैं।

कांतिलाल मंडांत, टिप्पणीकार



अनुलोम-विलोम हेमंत सोरेन गिरफ्तार



राजनीति का मतलब है, नीति-विशेष द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्ति करना। इसमें जिसकी लाठी, उसकी भैंस वाली कहवात ही चरितार्थ होती है, जिसकी पुष्टि हालिया घटनाक्रम भी करते हैं। इसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की खाई को काफी गहरा बना दिया है। गौर कीजिए, जहां-जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां-वहां ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं अपना जाल बिछा रही हैं। कुछ विशेषकर तो यह भी कहते हैं कि जो नेता सत्तारूढ़ दल से सम्बद्धता कर लेता है, वह पाक साफ बन जाता है, यानी उस पर जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका अर्थ है कि विपक्ष को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश भी गई है। चुनावी समीकरण को देखते हुए

यह संदेह गलत भी नहीं लगता। वैसे, झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, तभी से षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने की कोशिश शुरू हो गई थी। षड्यंत्रकारी यह भी नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय से कोई मुख्यमंत्री बने और लोगों के हक-अधिकारों को धरातल तक पहुंचाए। यही वजह है कि यहां को पिछली सरकार के समय कई घोटाले हुए और आदिवासियों को सरकारों नीतियों से बाहर रखने का प्रयास किया गया। स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बनाई गई और न ही इस बात को लेकर कोई ठोस प्रयास किया गया। वोटे की राजनीति करते हुए पिछली सरकार ने इस राज्य में बाहरी लोगों को आमद बढ़ा दी, जिससे जनसांख्यिकीय बदलाव की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, स्थानीय लोगों के हक में सेंधमारी की एक बड़ी वजह यह है कि मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से बहुत वाकिफ नहीं हैं। दक्षिण भारत में स्थानीयता को खत्म करने का कोई

भविष्य को मजबूती से निहारता बजट

यह बजट नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के प्रति उनके

आत्मविश्वास से उपजा है। केवल असुरक्षित सरकारें चुनावी नतीजों को बेहतर बनाने के लिए लुभावने कदम उठाती हैं।



होगी। भारत बेशक 7 ट्रिलियन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और निकट भविष्य में 10 ट्रिलियन तक भी पहुंचेगा। ऐसे लक्ष्य सामने हों, तो विकास की गति को कई प्रकार से बल मिलता है। चौथा, विकास गाथा में पहले के वर्षों की तुलना में ज्यादा राजस्व उछाल दिख रही है। इस वर्ष जीडीपी में करहिस्सेदारी 18 प्रतिशत से ज्यादा होने की संभावना है। यह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष व परोक्ष करों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ बेहतर राज्य जीएसटी को भी परिणाम है। राज्यों को अपने कर प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

तथ्य यह है कि राज्यों के लिए आवंटित अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपये में से 90 प्रतिशत से अधिक का उपयोग हुआ है, जो विकास को बढ़ाने वाली व्यवसायिकताओं में राज्यों के जिम्मेदारी पर व्यवहार को भी दर्शाता है। इससे राज्यों के राजकोषीय और ऋण प्रदर्शन में भी सुधार होगा।

पांचवां, यह बजट साल 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 35 प्रतिशत तक कम करके जलवायु परिवर्तन के

प्रति राष्ट्रीय स्तर पर तय योगदान को पूरा करने पर नए सिरे से जोर देता है। छत पर सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन जैसे कई उपायों की घोषणा की गई है, जो प्रशंसनीय है। इससे न केवल अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता को आदत पड़ेगी, बल्कि कुप्रबंधन की शिकार राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार और प्रतिस्पर्धा करने की प्रेरणा मिलेगी। विकास की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के साथ लोगों की साझेदारी भारतीय विकास गाथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नारी शक्ति, महिलाओं, युवा सशक्तिकरण और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ फसलों के लिए किसानों को बढ़ावा देने के उपायों पर नए सिरे से जोर दिया जाना भी विकसित भारत बनाने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण कारक होगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग की शक्ति में प्रधानमंत्री का विश्वास फिर झलका है। अनुसंधान एवं विकास में एक लाख करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण कोष का सृजन, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी और अनुसंधान-विकास में नवाचार न केवल युवा

रेल परिवहन

स्वच्छ यात्रा और विकास का इंजन बनेगी भारतीय रेल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहीं प्रत्यक्ष, तो कहीं परोक्ष रूप से रेलवे के कार्यांतरण की रूपरेखा पेश की। कुछ घोषणाएं तो बिल्कुल साफ हैं। मसलन, 40,000 बोगियों को बंदे भारत मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने की बात कही गई है। इससे निरसिद्ध यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा, ट्रेनों की गति बढ़ेगी और सुरक्षा मानक कहीं बेहतर होंगे। इन सबसे दुलाई व परिवहन खर्च में भी कमी आएगी, जिसके लिए अंतरिम बजट में पीएम गतिशक्ति योजना के तहत तीन नए रेलवे कॉरिडोर बनाने का एलान भी किया गया है। ये कॉरिडोर हिंम-ऊर्जा, सीमेंट व खनिज कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर।

अभी हमारे यहां दुलाई और परिवहन पर 14 फीसदी का खर्च आता है, जबकि अमेरिका में सात फीसदी। रेलवे जितना अधिक माल ढोएगा, वह लागत उतनी कम हो जाएगी, इसलिए बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे सुगम रेल यात्रा के साथ-साथ अधिकाधिक माल परिवहन भी संभव हो सकेगा।

इस बजट में दिसंबर, 2022 की राष्ट्रीय रेल योजना की झलक भी मिलती है। उस योजना में देश के कुल परिवहन में रेलवे को हिस्सेदारी 45 फीसदी तक करने की रूपरेखा भी बनाई गई थी। अभी जहां 27 फीसदी माल की दुलाई रेलवे करता है, वहीं सिर्फ 10 फीसदी यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाता है। इसे बढ़ाने के लिए रेलवे को पूर्णतः विद्युत्कृत करने, उच्च घनत्व वाले मार्गों को चार या छह लेन बनाने, बंदे भारत जैसी पुरु पुल ट्रेन लाने आदि प्रयासों की जरूरत बताई गई थी। इसके लिए व्यापक निवेश की दरकार थी। सुखद है कि बजट में इस पर जोर दिया ही गया है, दो दिन पहले वित्त मंत्रालय से आई रिपोर्ट में भी साल 2030 तक भारतीय रेलवे में 11 लाख करोड़ रुपये निवेश की बात कही गई है।

वित्त मंत्री ने मेट्रो और उप-नगरीय रेल सेवा के विकास की भी बात कही। अभी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में उप-नगरीय रेल सेवा चल रही है। बेंगलूरु में भी दो-तीन साल पहले इसका निर्माण शुरू किया गया था। अंतरिम बजट में इसके लिए भी प्रावधान है। उप-नगरीय रेल सेवाओं पर ध्यान देना काफी जरूरी भी है,

शक्ति का उपयोग करने में रचनात्मकता को सक्षम बनाएगा, बल्कि कई भावी चुनौतियों के लिए स्थानीय समाधान भी प्रदान करेगा। इससे भारत अपनी उत्पादकता में सुधार करते हुए प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।

आज विकास और व्यापक स्थिरता के बीच विषमता को संतुलित करना आसान नहीं है, पर यह अंतरिम बजट निर्णायक रूप से ऐसा करने की कोशिश करता है। इसी तरह, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और ऊर्जा बदलाव के बीच समझौता आसान नहीं है। विकास तेज करने और उत्सर्जन घटाने के बीच सही संतुलन बनाने के लिए कठिन विकल्पों की जरूरत पड़ती है। बजट में इन विकल्पों को बड़ी जिम्मेदारी से पेश किया गया है। प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, शिक्षा में बदलाव और मानव संसाधन क्षमता में वृद्धि रोजगार सृजन के नजरिये से एक अहम पहलू है। उद्योग के लिए प्रतिभावान और कुशल कार्यबल की उपलब्धता, सभी स्तरों पर स्कूलों में उम्र के अनुरूप सीखने के परिणाम और एक सेहतमंद व चुस्त आबादी अहम नीतिगत प्राथमिकताएं हैं, आने वाले वर्षों में भी ये चुनौतियां कायम रहेंगी।

अंतरिम बजट प्रतिबद्ध है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की रणनीति का पूरा खाका जुलाई में मुख्य बजट में शामिल किया जाएगा। निरसिद्ध, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम चल रहा है, पर चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च निवेश, बचत अनुपात, बढ़ी हुई उत्पादकता और क्रियान्वयन के साथ ही 7 प्रतिशत से ज्यादा की विकास दर की जरूरत है। इसमें राज्य सरकारों की भागीदारी की जरूरत है। राज्य सरकारों को हमारी विकास रणनीतियों में सक्रिय भागीदार बनाना विकसित भारत को साकार करने में एक अहम उद्येक होगा।

कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सभी हितधारकों के भारी समर्थन के साथ संघीय साझेदारी को गहरा बनाने में सक्षम होगा, जो समावेशी है, न्यायसंगत है, गरीबों की जरूरतों को पूरा करता है, जो लाभकारी रोजगार प्रदान करता है। हमें उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हुए अवसरों और युवाओं की जन्मजात नवाचार क्षमताओं को विकसित करना होगा। यह भारत के लिए वह क्षण है, जब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता।

(लेखक 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं)



विजय दत्त | सेवानिवृत्त अतिरिक्त सदस्य, रेलवे बोर्ड

क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई में हर दिन 60 लाख यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि दिल्ली मेट्रो में यह आंकड़ा योजना 35-40 लाख यात्रियों का है। इन रेल सेवाओं के विस्तार के लिए नई लाइनें बिछाने, दोहराकरण जैसे प्रावधान अंतरिम बजट में किए गए हैं। रिपेट रेल के विस्तार की भी बात की गई है।

अच्छी बात है कि भारतीय रेल पर्यावरण-सुधार में भी अपना योगदान दे रही है। कॉप-26 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को साल 2070 तक और रेलवे को 2030 तक 'नेट जीरो' उत्सर्जन बनाने की बात कही थी। नेट जीरो का अर्थ है कि कार्बन उत्सर्जन का पूरा तरह से अंत। इसके लिए जरूरी ही भारतीय रेलवे को पूरी तरह से विद्युत्कृत करना। हम इस साल ऐसा करने जा रहे हैं, और इस तरह भारतीय रेल विश्व की एकमात्र ऐसी रेल सेवा बन जाएगी, जो पूरी तरह से विद्युत्कृत होगी।

जाहिर है, इसमें चिन्ता हिस्सा अक्षय ऊर्जा का होगा, हम उतनी तेजी से नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे। अभी रेल में 13-14 फीसदी अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। अंतरिम बजट में इसे बढ़ाने का एलान वित्त मंत्री ने किया है। इसमें ऑफग्रीड विंड, यानी तटीय इलाकों में पवन ऊर्जा बनाने की योजना में सरकार द्वारा वित्तीय मदद की घोषणा फायदेमंद साबित हो सकेगी।

साफ है, सरकार एक तरफ रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, नई ट्रेनों की शुरुआत, रेलवे स्टेशनों के पुनरोद्धार जैसे कामों पर ध्यान दे रही है, तो दूसरी तरफ इसे विकास का इंजन भी बना रही है। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे से भी इसके संकेत मिलते हैं, क्योंकि इसे हरित बनाने में रेलवे की बड़ी भूमिका होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

विपक्ष को कमजोर करने की बड़ी साजिश

राजनीति का मतलब है, नीति-विशेष द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्ति करना। इसमें जिसकी लाठी, उसकी भैंस वाली कहवात ही चरितार्थ होती है, जिसकी पुष्टि हालिया घटनाक्रम भी करते हैं। इसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की खाई को काफी गहरा बना दिया है। गौर कीजिए, जहां-जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां-वहां ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं अपना जाल बिछा रही हैं। कुछ विशेषकर तो यह भी कहते हैं कि जो नेता सत्तारूढ़ दल से सम्बद्धता कर लेता है, वह पाक साफ बन जाता है, यानी उस पर जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका अर्थ है कि विपक्ष को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश भी गई है। चुनावी समीकरण को देखते हुए यह संदेह गलत भी नहीं लगता। वैसे, झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, तभी से षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने की कोशिश शुरू हो गई थी। षड्यंत्रकारी यह भी नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय से कोई मुख्यमंत्री बने और लोगों के हक-अधिकारों को धरातल तक पहुंचाए। यही वजह है कि यहां को पिछली सरकार के समय कई घोटाले हुए और आदिवासियों को सरकारों नीतियों से बाहर रखने का प्रयास किया गया। स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बनाई गई और न ही इस बात को लेकर कोई ठोस प्रयास किया गया। वोटे की राजनीति करते हुए पिछली सरकार ने इस राज्य में बाहरी लोगों को आमद बढ़ा दी, जिससे जनसांख्यिकीय बदलाव की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, स्थानीय लोगों के हक में सेंधमारी की एक बड़ी वजह यह है कि मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से बहुत वाकिफ नहीं हैं। दक्षिण भारत में स्थानीयता को खत्म करने का कोई

आमप्रकाश, टिप्पणीकार

खराब मौसम के कारण सभी विधायकों को सर्किट हाउस लौटना पड़ा विधायकों को लेकर हैदराबाद के लिए नहीं उड़ सका विमान के लिए नहीं उड़ सका विमान

झारखंड

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच महागठबंधन के 38 विधायक तेलंगाना के हैदराबाद जाने के लिए विमान में बैठे, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान उड़ान नहीं भर सका। सभी विधायकों को चार्टर प्लेन में एक चंटा बैठने के बाद उतरकर फिर से सर्किट हाउस लौटना पड़ा। अब शुक्रवार को हैदराबाद जाने की फिर से तैयारी की जा सकती है।



रांची में गुरुवार की देर शाम विमान से हैदराबाद जाने को निकले झामुमो नेता हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन व अन्य विधायक।

राज्य में स्थिर सरकार देने में सक्षम: चंपई

दावा
महागठबंधन विधायकों को गुरुवार की देर शाम दो चार्टर विमान से रांची हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने के लिए लेकर आया गया था। उन्हें रात में बेगमपेट हवाई अड्डे पर उतरकर सीधे उन्हें बंजारा हिल्स स्थित होटल ताज कृष्णा ले जाया जाना था। तेलंगाना में ए. रेवत रेड्डी की नवनियुक्त कांग्रेस सरकार ने विधायकों के लिए व्यवस्था की है। महागठबंधन के विधायकों को एकजुट रखने और किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त नहीं हो इसको देखते हुए विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा रहा था।

गठबंधन मजबूत है। कोई कुछ नहीं कर सकता। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था। वह बहुमत के आंकड़े से अधिक है। वह राज्य में स्थिर सरकार देने में सक्षम है।

विधायक और राज्य की जनता राज्यपाल से उम्मीद करती है कि जल्द ही एक लोकप्रिय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे और राज्य को भ्रम की स्थिति से बाहर निकालेंगे।
बसंत साधु गाए, सीता का भी समर्थन : महागठबंधन में शामिल झामुमो के जिन चार विधायकों को

लेकर संशय की स्थिति बताई जा रही थी उनमें से बसंत सोरेन महागठबंधन के अन्य विधायकों के साथ समर्थन में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने कहा कि वह

महागठबंधन सरकार को ही समर्थन देंगे। वह दिल्ली से लौट कर रांची आ गई हैं। उन्होंने कहा कि वह दुर्गा सोरेन के खून पसीने से खड़ी पार्टी को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती।

साजिश के तहत फंसाया, लड़ूंगा और जीतूंगा : हेमंत

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले झारखंड की जनता के नाम अपना संदेश रिकॉर्ड किया। यह वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया में चलता रहा है। हेमंत के अनुसार जिस जमीन को लेकर उन पर आरोप लगाए गए हैं, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हेमंत ने कहा कि जाली कागज बनाकर, फर्जी शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचने वाले कामयाब हो रहे हैं। लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल सत्य की विजय होगी। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की खबरें आंफेंगी। विरोधियों के नापाक इरादे फिलहाल कामयाब हो रहे हैं। वह अपनी पीठ थपथपाएंगे। झारखंड की जनता काफी संवेदनशील और कर्मठ है। ईमानदारी के साथ वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्हें उम्मीद है कि इस लड़ाई में सभी का सहयोग मिलेगा।



शिवू सोरेन का पुत्र हूँ, संघर्ष मेरे खून में

हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी की घिटा नहीं है। वह शिवू सोरेन के पुत्र हैं। संघर्ष उनके खून में है। वह संघर्ष करेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे भी। किसी खास मंसूबे की वजह से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया है। उनके पास समय बहुत कम है। हाल में ही राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है। अब यह झारखंड को भी षड्यंत्र का शिकार बना रहे हैं।

सरकार बनाकर जनता की सेवा कर रहा था। आज लगता है कि यह वक्त उनके लिए खल हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी।

सोरेन की याचिका पर शीर्ष कोर्ट में सुनवाई आज होगी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धन शोधन के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस याचिका पर शुक्रवार को विस्तार से सुनवाई की जाएगी। ईडी ने सोरेन को बुधवार की रात को गिरफ्तार किया था।

झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ पहले उच्च न्यायालय में याचिका दायित्व की थी। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई करने का फैसला किया था। हालांकि इस बीच सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायित्व कर ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिषेक मनु सिंघवी ने याचिका का उल्लेख करते हुए सुनवाई का आग्रह किया। विशेष पीठ का गठन: उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार को तीन जज की एक विशेष पीठ का गठन किया।

नीतीश सरकार 12 को विश्वास मत प्राप्त करेगी

बिहार
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार अब 12 फरवरी को विश्वास मत प्राप्त करेगी। 13 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। दरअसल, विधानमंडल का बजट सत्र अब पूर्व निर्धारित 10 फरवरी की जगह 12 फरवरी से होगा। इसलिए विश्वासमत के लिए पहले से तय तिथि में बदलाव किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आलंकर 9 को शाम से 11 फरवरी तक बिहार में नहीं हैं। राज्यपाल ने सत्र के कार्यक्रम में बदलाव करने का निर्देश सरकार को दिया है। इसके मद्देनजर अब सत्र की नई तिथि तय की गई है। राजस्व न के पत्र आने के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने

1 मार्च तक सत्र, कुल 11 बैठकें होंगी
विधानमंडल का बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 11 बैठकें होंगी। पहले दिन सोमवार को ही राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आलंकर सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। संयुक्त सत्र के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार विश्वास-मत हासिल करेगी। साथ ही सदन में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया जाएगा। इसी दिन नए विधानसभा अध्यक्ष का भी पदभार ग्रहण होगा। दूसरे दिन 13 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। एक अग्रे मार्ग पहुंचे। वहां इसको लेकर बैठक हुई। इस बातचीत में विजय कुमार चौधरी भी शामिल थे।

सजा सुनाने वाले जज को धमकी के मामले में चार पकड़े

अलप्पुझा (केरल)। भाजपा नेता की हत्या मामले में फैसला सुनाने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को धमकी देने के मामले में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकाारी ने पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी। आरोपियों को पंचनाम मन्नाचरी निवासी नसीरमोन, मंगलापुरम निवासी रफी, अलापुझा निवासी नवास नैन और अंबालापुझा निवासी शाजहां के रूप में हुई है। कुल पांच मामलों दर्ज किए गए हैं और चार मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम नियुक्त की गई है। केरल पुलिस ने मार्गदर्शक आतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम वीजी श्रीदेवी को ऑनलाइन दी जा रही धमकियों को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी।

कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1993 मानी

उत्तर प्रदेश
मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। छजलैट बवाल केस में सजा पाए आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। जिला जज अदालत ने गुरुवार को अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1993 मानी है। इससे बचाव पक्ष का दावा भी खारिज हो गया है। अब्दुल्ला आजम की उम्र निर्धारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई कर रहे जिला जज ने सुनवाई कर 37 पेजों का आदेश जारी किया। कोर्ट में लखनऊ नगर निगम और क्वीन मैरी अस्पताल के जन्मतिथि के साथ दाखिल किए गए थे। अब्दुल्ला की जन्मतिथि की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी। अब्दुल्ला की उम्र निर्धारण के मामले को जिला जज डा. अजय कुमार

दुष्कर्म मामले में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री चिन्मयानंद दोषमुक्त

शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद शिष्या से दुराचार और धमकी देने के 12 साल पुराने मामले में दोषमुक्त हो गए हैं। शाहजहांपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर तीन ने गुरुवार को मुकदमे से चिन्मयानंद को बरी कर दिया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने वाली शिष्या अपने बयान से मुकर गई थी। उसने कोर्ट में कहा था कि चिन्मयानंद ने उसके साथ कभी कोई अपराध नहीं किया। इसी बयान के आधार पर चिन्मयानंद बरी किए गए। 30 नवंबर 2011 को स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने शाहजहांपुर के थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शिष्या ने चिन्मयानंद पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कर्मचारियों की मदद से मुमुक्षु आश्रम में उसे बंधक बनाकर दुराचार किया था।

अंत्योदय के तहत चीनी पर सब्सिडी दो वर्ष के लिए बढ़ी

कैबिनेट फैसले
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) में शामिल 1.89 करोड़ परिवारों को राशन दुकानों के जरिये बांटी जाने वाली चीनी पर सब्सिडी को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी पर सब्सिडी की योजना को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सब्सिडी योजना के तहत केंद्र राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है। इसकी खरीद एवं वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की होती

ई-कोर्ट के लिए 825 करोड़ रुपये आवंटित
नई दिल्ली। निचली अदालतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने से संबंधित ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए इस वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान के बाद 825 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगले वित्त वर्ष के लिए 1,500 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई राशि आवंटित की गई है। तीसरे चरण के लिए 7,210 करोड़ रुपये के वित्तीय परियोजना को पिछले साल सितंबर में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। है। इस मंजूरी से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि में 1,850 करोड़ से अधिक का लाभ दिए जाने की उम्मीद है। योजना से 1.89 करोड़ एएवाई परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है।

रोजनामचा

पं. राधेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य
मेघ : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। किसी दूसरे स्थान पर जाने का योग है।
वृष : मन प्रसन्न तो रहेगा। परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। शैक्षिक कार्यों में कुछ सुधार होगा। कारोबार पर ध्यान दें। लाभ के अवसर मिलेंगे, पर मेहनत ज्यादा होगी।
मिथुन : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के अवसर मिल सकते हैं।
कर्क : मन अशांत हो सकता है। भावनाओं को वश में रखें। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। आय वृद्धि होगी।

रिंह : कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। वाणी में मधुरता रहेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं।
कन्या : आत्मविश्वास मरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, पर धैर्यशीलता बनाए रखें। शैक्षिक कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।
तुला : कारोबार में विस्तार हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। रहन-सहन अत्यवस्थित रहेगा। लाभ में वृद्धि होगी। धार्मिक स्थान पर जाने का योग है।
वृश्चिक : मन प्रसन्न तो रहेगा, पर संयत रहे। संपत्ति में वृद्धि होगी। किसी मित्र के सहयोग से किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में लाभ के योग।

धनु : किसी मित्र का आगमन हो सकता है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। परिवार के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है।
मकर : संयत रहें। कारोबार में सुधार होगा। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। रहन-सहन अत्यवस्थित रहेगा।
कुंभ : कारोबार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। लेखन कार्यों से व्यस्तता बढ़ेगी। आय के साधन भी बनेंगे।
मीन : नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी, पर खर्च भी बढ़ेगा।

वर्ग पहली : 7501
ऊपर से नीचे
1. निपटाना; संपन्न करना (2,3)
2. अजीर्ण; बदहजमी (3)
3. चानहना; तरजीह देना; वरीयता देना (3,3)
4. खिसकना; दूर होना; स्थगित होना (4)
5. औषध; खारी; द्रोणी; लवण (3)
6. समझौता करना; वायदा करना (3,3)
7. कर की दर तय करना; राजस्व प्राप्ति हेतु आदेश देना (2,3)
8. निर्वाचन के लिए मत देने की क्रिया (4)
9. गड्डे में रख कर मिट्टी से ढकना; छिपा कर रखना; दबाना; दफनाना; धंसाना (3)
10. नदी का ऊंचा तट; सहमति; वायदा; चैन (3)
हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली (उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहली : 7500
बाएं से दाएं
3. बाने वाली हंसी; निदासूचक हास; दिल्लीगी; हंसी-ठट्टा (4)
6. कड़पान; कठोरता; कुरकुरापन (5)
8. चटक-मटक; आभा; काँति; दीप्ति; शान (3,3)
9. तारा; नक्षत्र; आंख की पुतली; कर्णधार; तारने वाला; पर उतारने वाला (3)
11. अप्रसन्न; रुष्ट (3)
12. पूरा करने वाला; पूर्णिकता (3)
16. एक देवी; विश्वामित्र के पुत्र का नाम (3)
17. चमक-दमक; ठाट-बाट; शान; सजधज; चकाचौंध (3,3)
19. विरोध में जोर-जोर से बोलना; आंदोलन करना; उद्घोष करना; प्रदर्शन करना (2,3)
20. आदमी-औत; नर-नारी; महिला-पुरुष (2,2)

सुडोकू : 7485
खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहली है यह। ऊपर नी-नी खानों के नी खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएँ इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएँ आएँ। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएँ हों। पहली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 7484

मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सात जज वाली संविधान पीठ ने आठ दिन तक सुनीं दलीलें एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर संविधान पीठ का फैसला सुरक्षित

सुनवाई

■ प्रभात कुमार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा, हमें एक बात चिंतित कर रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के लिए एएमयू अधिनियम 1981 में किए गए संशोधन संस्थान के 951 की स्थिति को बहाल नहीं करते। दूसरे शब्दों में हम इस संशोधन को संसद द्वारा आधा-अधुरा काम भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास एएमयू को 1951 से पहले के अधिनियम या 1920 के अधिनियम की स्थिति को बहाल करने की शक्ति थी।

प्रथम विश्व युद्ध में जो लड़े, क्या वे अंग्रेजों के वफादार थे: सिब्लल

एएमयू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्लल ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा, एक धर्मनिरपेक्ष देश में जो बहुलता के लिए समर्पित है, समावेशी भारत के लिए प्रतिबद्ध है और हम यह तर्क दे रहे हैं कि यह (एएमयू) कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं था। सिब्लल ने केंद्र की उस दलील के महंजनर दलील दी कि जिसमें कहा गया था कि एएमयू कभी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रहा। सिब्लल ने कहा कि प्रतिवादियों की ओर से तर्क दिया गया कि हम (एएमयू) की स्थापना करने वाले) अंग्रेजों के प्रति वफादार थे तो क्या प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े, क्या वे भी अंग्रेजों के वफादार थे। सिब्लल ने इसी तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय और आईएसए अधिकारी भी अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, क्या यह एक तर्क है? यह एक सांप्रदायिक तर्क है।

यह है मामला

सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने 1967 में अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि चूंकि एएमयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। 1875 में स्थापित इस संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब वापस मिल गया, जब संसद ने 1981 में एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित किया। जनवरी 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा मिला था। केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली संसद सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। एएमयू ने भी चुनौती दी थी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पूर्ववर्ती संसद सरकार द्वारा दायर अपील वापस ले लें। इसने एस अजीज बाशा मामले में शीर्ष अदालत के 1967 के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया था कि एएमयू अल्पसंख्यक नहीं था, क्योंकि यह सरकार द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय विश्वविद्यालय था।



पारदीवाला, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। संविधान पीठ ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ अजीज बाशा बनाम भारत संघ के मामले में पारित फैसले के बाद जहां तक हम

समझते हैं कि 1981 में कानून में किया गया संशोधन एएमयू प्रशासन में मुस्लिमों की आवाज को लाना था। संविधान पीठ के समक्ष एएमयू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा, यदि 1981 में कानून में किया गया संशोधन आधा-अधुरा था तो इस बारे में दो

प्रतिक्रियाएँ हैं। पहला अदालत में संख्यात्मक तर्क, लेकिन हमें अदालत की तरफ नहीं, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को देखना है और वे बड़े पैमाने पर हैं। दूसरा, अब अदालत ने जो जोड़ा वह भारत में धर्म, सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देना था।



पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोगों से मिलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी। • प्रेस

पश्चिम बंगाल में लोगों से मिले राहुल



भारत जोड़ो न्याय यात्रा 19वाँ दिन
कोलकाता, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पहुंची। राज्य में इसका उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। नेताओं ने

कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सहयोगी तुणमूल कांग्रेस शासित राज्य के जलपाईगुड़ी, मालदा और मुर्शिदाबाद में जनसभा और प्रवास व्यवस्था की अनुमति के लिए काफी पेशानी का सामना करना पड़ा। न्याय यात्रा ने मालदा जिले के रतुआ, बर्दमान जिले के देवीपुर के रास्ते बुधवार को पश्चिम बंगाल में फिर से प्रवेश किया था। गत सोमवार को पश्चिम बंगाल में यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया था।

यात्रा में शामिल होना न्याय की लड़ाई का हिस्सा: भाकपा

भाकपा की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम ने मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में न्याय यात्रा में शामिल होते हुए दावा किया कि देश न्याय और अन्याय के बीच विभाजित है। उन्होंने कहा कि यात्रा में वाम दल का शामिल होना इस लड़ाई का हिस्सा है।

सीआरपीएफ जवान विस्फोट में घायल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गुरुवार को नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट में सीआरपीएफ का एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोटिया के निकट हुआ।

'मानदंड पूरे करने पर मिलेगा बकाया'

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि राज्य का सारा बकाया केंद्र द्वारा चुका दिया जाएगा, बशर्त बंगाल सरकार केंद्र के निर्धारित मानदंडों को पूरा करे। गवर्नर सी.वी. आनंद बोस ने गुरुवार को यह बात नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद कही।

अशनीर गोवर ने हाई कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली। भारत के पूर्व एमडी अशनीर गोवर और उनकी पत्नी ने घोषणा की है कि वे जलसाजी मामले में उनके खिलाफ जारी लुका आइट नोटिस को रद्द करने की मांग को लेकर रायपुर में गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में लगे हैं।

अपना बिजनेस | विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में तेजी आई

उत्साहजनक

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि जनवरी में चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। नए टेकों से वृद्धि को बढ़ावा मिला। गुरुवार को जारी मासिक सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है।

चार महीनों में सबसे मजबूत बढ़त

सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय सामान उत्पादकों को दिए गए नए टेके जनवरी में तेज गति से बढ़े और यह चार महीनों में सबसे मजबूत वृद्धि है। विपणन प्रयासों और मांग में उछाल से वृद्धि को बढ़ावा मिला। अंतरराष्ट्रीय बिक्री भी तेज गति से बढ़ी। सामान उत्पादकों ने आफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पश्चिम एशिया और अमेरिका में फैले ग्राहकों से मजबूत मांग की जानकारी दी।

मैं 50 से ऊपर का मतलब विस्तार से है। वहीं, 50 से कम का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है। एचएसबीसी के अर्थशास्त्री इनेस लैम ने कहा कि भारत के विनिर्माण पीएमआई से जनवरी में विनिर्माण गतिविधि में तेजी

को बात सामने आई है। उत्पादन मांग मजबूत है। घरेलू टेके, निर्यात टेकों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय टेके में विस्तार की दर पिछले अक्टूबर के बाद से सबसे तेज रही।

यात्री वाहनों की बिक्री ने जनवरी में रफ्तार पकड़ी

मुंबई, एजेंसी।

जनवरी में शानदार बिक्री दर्ज करते हुए वाहन विनिर्माताओं ने नए साल की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की। अधिकांश कंपनियों ने एक साल पहले की तुलना में पिछले महीने अधिक बिक्री की है।

भारति सुजुकी की कुल बिक्री में 15.5 फीसदी का उछाल, टाटा मोटर्स में छह फीसदी का इजाफा

भारति सुजुकी की इंडिया, टाटा मोटर्स, हुंदै मोटर इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की बिक्री जनवरी, 2024 में साल भर पहले की तुलना में बढ़ी है। भारति सुजुकी की बिक्री में अगले महीने अपना रिकॉर्ड बिक्री आंकड़ा हासिल करने में सफल रही। कंपनी की कुल वाहन बिक्री जनवरी में 15.5 प्रतिशत बढ़कर

सोना 100 रुपये मजबूत, चांदी टूटी

नई दिल्ली, एजेंसी। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 100 रुपये की बढ़त के साथ 63,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 63,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, चांदी की कीमत 600 रुपये लुढ़ककर 76,100 रुपये प्रति किलोग्राम रह गयी।

रुपये में छह पैसे की बढ़ोतरी दर्ज

मुंबई, एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय बाजार में गुरुवार को अमेरिका मुद्रा के मुकाबले रुपया छह पैसे की तेजी के साथ 82.98 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिम बजट में राजकोषीय मजबूती पर जोर और उधारी कम किए जाने के संकेत के बाद रुपये में तेजी आई। रुपया बुधवार को 83.04 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

कपड़ा निर्यात प्रोत्साहन योजना आगे जारी रहेगी

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को परिधान, कपड़ा और मेड-अप के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना (आरओएससीटीएल) को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को 31 मार्च 2026 तक के लिए मंजूरी दी

उपकरणों में छूट योजना का उद्देश्य परिधान/कपड़ा और मेड-अप के निर्यात पर शुल्क वापसी योजना के तहत प्रदान की गई छूट के अलावा राज्य और केंद्रीय करों और उपकरणों की भरपाई करना है। यह कदम एक स्थिर नीति व्यवस्था प्रदान करेगा, जो दीर्घकालिक व्यापार योजना के लिए जरूरी है।

UTTARAKHAND CIVIL AVIATION DEVELOPMENT AUTHORITY
Doon Helidrome Dehradun, Sahasthradhar Road, P.O Kulhan, Pincode 248013 Tel. 0135 2888981
Letter No. 201/UCADA/Hemkund/2024 Date: 01 Feb, 2024

TENDER FOR SELECTION OF HELICOPTER SHUTTLE SERVICE OPERATORS FOR ROUTE GOVINDGHAT-GHANGARIA

- Date of downloading tender document : 03/02/2024 Time 17:00 HRS at uktenders.gov.in
- date of Pre-bid meeting : 08/02/2024 Time 11:30 HRS
- Last date for submission of documents : 15/02/2024 Time 16:00 HRS physically at UCADA
- Last Date for submission of Tender : 15/02/2024 Time 15:00 HRS
- Date of opening of Technical Bid : 15/02/2024 Time 16:00 HRS
- Date of opening of financial bids:- Shall be intimated later by email to the technically qualified bidders.

For more details, please visit uktenders.gov.in / official website www.ucada.in / Uttarakhand Civil Aviation Development Authority, Doon Helidrome, Mussoorie by pass P.O- Kulhan, Dehradun, Uttarakhand 248013 CEO, (UCADA)

कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान
सी०जी०सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ-226002
(उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्यशास्त्री संस्थान)
Website: <https://cancerinstitute.edu.in> Email: jdmm.sscih@gmail.com

Custom GeM Bid Notice
सूचित किया जाता है कि कस्टम GeM बिड संख्या GEM/2024/B/4476668 दिनांक 31.01.2024 को Bid for Services - In house BMW Management Services के लिए GeM पोर्टल पर अपलोड किया गया है। समस्त इच्छुक सेवाप्रदाताओं/ निविदाकर्ताओं से निविदा की शर्तों के अनुसार जेम पोर्टल बिड आमंत्रित की जाती है। निदेशक, के.एस.एस.सी.आई., लखनऊ बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

नोट:
1. जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिनांक 16.01.2024 को दोपहर 2:00 बजे प्री बिड मीटिंग आयोजित की जायेगी, सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वह ऑनलाइन प्री बिड मीटिंग में प्रतिभाग करने हेतु लिंक प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी office.sscih@gmail.com पर अपने ईमेल एड्रेस अग्रसारित करने का कष्ट करें। निविदा दस्तावेज संस्थान की वेबसाइट www.cancerinstitute.edu.in पर उपलब्ध है।
AdvT No. : KSSSCI/PRO-41/2023-24 निदेशक

गाजियाबाद नगर निगम
(I.S.O. 14001, 18001 एवं 19001 प्रमाणित संस्था)
पत्रांक सं०-158/नजारत विभाग/2023-24 दिनांक- 29.01.2024
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सक्षम ठेकेदारों से नजारत विभाग में आने वाले लोकसभा चुनाव-2024 में सभी मतदेय स्थलों (प्रत्येक स्थल) पर पोलिंग पार्टी हेतु दो दिवस के लिये किराये के आधार पर रजार्ड व गढ़े उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश ई-निविदा की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 से दिनांक 18.02.2024 तक सायं 3:00 बजे तक आमंत्रित है। उक्त कार्य की तकनीकी निविदा दिनांक 18.02.2024 को सायं 04:00 बजे खोली जायेगी। निविदा शुल्क घनराशि गाजियाबाद नगर निगम के खाता सं०- 628601041088 IFSC Code- ICIC0006286 ICICI Bank R.D.C. Rajnagar Ghaziabad में जमा कराकर उसकी रसीद की छायाप्रति एवं धरोहर राशि की आरटी. जी.एस. /एफ०डी०आर० जो कि लेखाधिकारी गाजियाबाद नगर निगम के नाम पर बन्धक होगी, को वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य हेतु नियम व शर्तें एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट प्राप्त की जा सकती है।
नजारत प्रभारी गाजियाबाद नगर निगम

कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान
सी०जी०सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ-226002
(उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्यशास्त्री संस्थान)
Email: jdmm.sscih@gmail.com

Custom GeM Bid Notice
दिनांक: 31.01.2024
सूचित किया जाता है कि कस्टम GeM बिड संख्या GEM/2024/B/4476812 दिनांक 31.01.2024 को Bid for Services-Bio Medical waste Management Treatment Facility Services के लिए GeM पोर्टल पर अपलोड किया गया है। समस्त इच्छुक सेवाप्रदाताओं/ निविदाकर्ताओं से निविदा की शर्तों के अनुसार जेम पोर्टल बिड आमंत्रित की जाती है। निदेशक के.एस.एस. सी. आई., लखनऊ बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

नोट:
1. जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिनांक 16.01.2024 को दोपहर 3:00 बजे प्री बिड मीटिंग आयोजित की जायेगी, सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वह ऑनलाइन प्री बिड मीटिंग में प्रतिभाग करने हेतु लिंक प्राप्त करने के लिये ईमेल आईडी office.sscih@gmail.com पर अपने एड्रेस अग्रसारित करने का कष्ट करें। निविदा दस्तावेज संस्थान की वेबसाइट cancerinstitute.edu.in पर उपलब्ध है।
Adv.No: KSSSCI/PRO-40/2023-24 निदेशक

साठ के बाद गरिमामय जीवन के लिए
6 करोड़ से अधिक
अभिदाता अटल पेंशन योजना में पंजीकृत हो चुके हैं

“हमारी सरकार तीन पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, बैंक रहित को बैंक की सुविधा प्रदान करना, फण्ड से वंचित लोगों को फण्ड उपलब्ध कराना एवं असुरक्षित को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। हमारा प्रयास है कि देश के सभी नागरिक एक सुराहाल और मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करें”
श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार

आप भी एपीवाई से जुड़े और आजीवन गारंटीड पेंशन सहित दो अन्य लाभ भी उठाएँ

- 1000/- या 2000/- या 3000/- या 4000/- अथवा 5000/- रुपये प्रति माह तक आजीवन पेंशन की गारंटी
- अभिदाता की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को आजीवन समान पेंशन
- पति/पत्नी की मृत्यु के पश्चात नामित को 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि की वापसी

अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं।

आज ही जुड़े, नुगतान कम करें	आयु	पेंशन स्लैब (₹)	नुगतान राशि (₹)	पेंशन स्लैब (₹)	नुगतान राशि (₹)
	18	1000	42 प्रति माह	5000	210 प्रति माह
	40	1000	291 प्रति माह	5000	1454 प्रति माह

आज ही अपने नजदीकी डाकघर/बैंक में संपर्क करें या 1800 110 069 प्र कॉल करें या www.pfrda.org.in पर जाएं।

ओलंपिक वर्ष में खेलों के लिए 3442 करोड़ रुपये मिले



नई दिल्ली, एजेंसी। खेल मंत्रालय को गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट में 3,442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पेरिस ओलंपिक को देखते हुए इसमें पिछले साल की तुलना में 45.36 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया। पिछले बजट में खेलों के लिए 3,396.96 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश का मुख्य ध्यान पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक खेलों पर है। खेलों में 20 करोड़ की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल इसके लिए एक हजार करोड़ दिए गए थे जो संशोधित बजट में घटाकर 880 करोड़ कर दिए गए थे।

45 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट में इजाफा किया गया, पिछले साल 3396.96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे

900 करोड़ रुपये खेलों के लिए आवंटित किए गए

सीतारमण ने प्रज्ञाननंदा को सराहा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान खिलाड़ियों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, देश को हमारे युवाओं पर गर्व है जो खेलों में नई ऊंचाइयों छू रहे हैं। चीन में पिछले साल हुए एशियाई और पैरा एशियाई खेलों में अब तक की सबसे अधिक पदक तालिका उच्च आत्मविश्वास के स्तर को दर्शाती है। शतरंज की प्रतिभाशाली खिलाड़ी और हमारे रेटिंग में नंबर एक खिलाड़ी आर प्रज्ञाननंदा ने 2023 में मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर दी। आज देश में 80 से ज्यादा ग्रैंड मास्टर हैं जबकि 2010 में 20 से अधिक थे।

साई को 822 करोड़ : भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के बजट में पिछले साल की तुलना में 26.83 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह 822 करोड़ किया गया जो पिछले साल 795.77 करोड़ रुपये था। राष्ट्रीय खेल महासंघों का बजट 15 करोड़ रुपये बढ़ाकर इस साल 340 करोड़ रुपये किया गया है।



खिलाड़ियों के भते में कटौती की गई

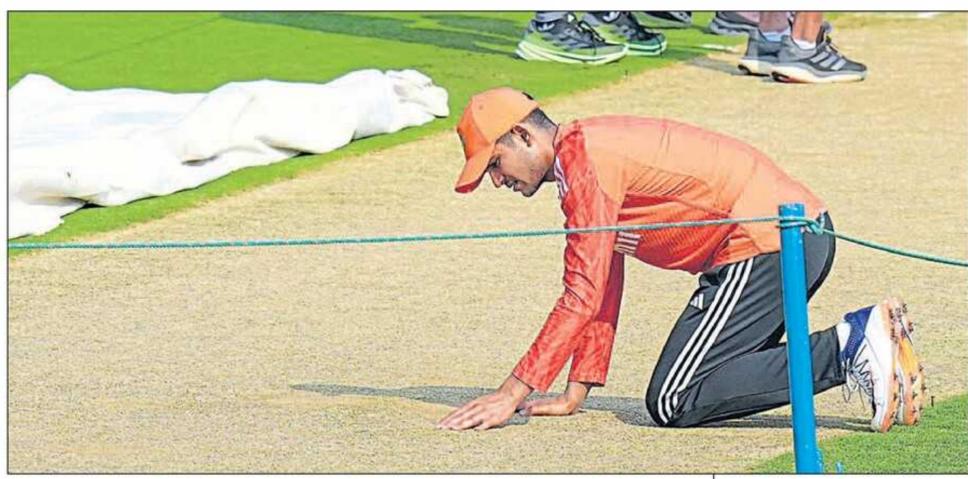
नई दिल्ली। खिलाड़ियों को मिलने वाले भते के बजट को 84 करोड़ से घटाकर 39 करोड़ कर दिया गया है। राष्ट्रीय खेल विकास कोष के बजट को 46 करोड़ से कम करके 18 करोड़ रुपये किया गया है। इसी तरह, राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र का बजट 10 करोड़ रुपये से घटाकर आठ करोड़ रुपये कर दिया गया। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के लिए पिछली बार के 83.21 करोड़ रुपये के बजट में इजाफा हुआ है। अब यह 91.90 करोड़ रुपये हो गया है। राष्ट्रीय डॉपिंग रोधी एजेंसी को अंतरिम बजट में 22.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो 2023-24 वित्तीय वर्ष में 21.73 करोड़ रुपये का था।

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से, मेजबान बराबरी के लिए तो मेहमान बढ़त बनाने के लिए मैदान पर उतरेंगे

टीम इंडिया के सामने पलटवार की चुनौती



विशाखापत्तनम, एजेंसी। भारतीय टीम के सामने हैदराबाद का किला गंवाने के बाद अब अजेय विशाखापत्तनम बचाने की चुनौती होगी। रोहित एंड कंपनी के लिए पलटवार कर इंग्लैंड की बेखोफ बैजबॉल शैली से पार पाना आसान नहीं होगा। वो भी तब जब कोहली और केएल राहुल जैसे उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मैच में नहीं होंगे। दूसरी ओर अंग्रेजों ने शुरूवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन को एकादश में शामिल कर भारत पर दूसरे चार की तैयारी कर ली है।



लीच चोटिल, शोएब बशीर देंगे पहला टेस्ट

वीजा दिवसों के चलते देर से यहां पहुंचे पाक मूल के 20 साल के स्पिनर शोएब बशीर इंग्लैंड के लिए टेस्ट में पर्दापण करेंगे। वह जैक लीच की जगह लेंगे जो चोटिल होने के कारण मैच में नहीं खेल पाएंगे। वहीं पहले टेस्ट में कोई विकेट नहीं लेने वाले मार्क वुड की जगह अनुभवी एंडरसन टीम में एकमात्र तेज गेंदबाज होंगे।

इंग्लैंड की अंतिम एकदश

क्राउली, डकेट, पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, स्टोक्स, फोक्स, रेहान, हार्टले, बशीर, जेम्स एंडरसन।

विशाखापत्तनम में गुरुवार को पंच का मुआयना करते शुभमान गिल।

पिच रिपोर्ट
बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है। इसके साथ ही यहां स्पिनरों का भी बोलबाला रहा है।

मौसम
सामान्य गर्मी रहेगी लेकिन मुकाबले के तीसरे दिन बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।

02 मैच यहां पर अब तक खेले हैं। इनमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है।

05 साल बाद यहां टेस्ट खेला जाएगा। अक्टूबर 2019 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 230 रन से धोया था।

16 सर्वाधिक विकेट अरिश्वन ने विजाग में दो मैचों में चटकाए हैं।

03 टेस्ट खेलने का अनुभव है इंग्लैंड के दो स्पिनरों रेहान और हार्टले को, बशीर पर्दापण करने को तैयार।

भारतीय बल्लेबाजों का घर में प्रदर्शन

खिलाड़ी	मैच	रन	औसत	सर्वोच्च	100/50
रोहित	25	2065	64.53	212	8/6
श्रेयस	08	478	36.76	105	1/3
गिल	09	440	29.33	128	1/2
यशस्वी	01	95	47.05	80	0/1

विजाग में बोलता है रोहित का बल्ला
विजाग में रोहित का बल्ला खूब बोल रहा है। वह यहां तीन सौ से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट की दो पारियों में रिकॉर्ड 151.50 की औसत से 303 रन बनाए हैं। वह इस मैदान पर दो शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।

आर अरिश्वन 500 से चार विकेट दूर

दिग्गज ऑफ स्पिनर अरिश्वन 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बनने से सिर्फ चार विकेट दूर हैं। वह 96 मैच में 2.77 की औसत से 496 विकेट ले चुके हैं। चार और विकेट लेते ही वह अनिल कुंबले (619 विकेट, 132 मैच) के क्लब में शामिल हो जाएंगे। चंद्रशेखर को पछाड़ेंगे: अरिश्वन दो और विकेट लेते ही इंग्लैंड के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय बन जाएंगे। 20 मैच में 94 विकेट ले चुके अरिश्वन बीएस चंद्रशेखर (95 विकेट, 23 मैच) का 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दोनों टीमों की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड एंडरसन (139 विकेट, 35 मैच) के नाम है।

एंडरसन को 700 के लिए चाहिए 10 विकेट

जेम्स एंडरसन 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज और कुल तीसरे खिलाड़ी बनने से दस विकेट दूर हैं। 41 वर्षीय इस पेसर के नाम 183 मैच में 2.78 की इकोनॉमी से 690 विकेट हैं। अभी तक श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन (800 विकेट, 133 मैच) और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न (708 विकेट, 145 मैच) ही सात सौ या उससे अधिक विकेट ले पाए हैं।

अकेले रूट के टीम इंडिया से 447 ज्यादा रन

दूसरे टेस्ट में भारत की जो 17 सदस्यीय टीम है उसने मिलकर कुल 10,702 बनाए हैं। जबकि इंग्लैंड के जो रूट ने ही इन सभी से 447 ज्यादा रन बनाए हैं। रूट ने 136 टेस्ट में और 30 शतकों से 11,447 रन बनाए हैं।

'सुपर सिक्स' में जीत का 'पंच' जड़ने उतरेंगे युवा

अंडर-19 क्रिकेट
ब्लूमफोर्टेन। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय क्रिकेट टीम शुरूवार को यहां आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के ग्रुप वन के आखिरी सुपर सिक्स मैच में नेपाल से भिड़ेगी। इसमें भारत का लक्ष्य जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरने का होगा। भारत शीर्ष पर : सुपर सिक्स से शीर्ष दो टीमों सेमीफाइनल खेलेंगी। पाकिस्तान (प्लस 1.06) और भारत

प्रो लीग हॉकी : भारत की पहली भिड़ंत स्पेन से

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान न्यूज़। दक्षिण अफ्रीका में चार देशों के टूर्नामेंट के साथ सत्र की शुरुआत करने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम की अब घर में एफआइएच प्रो लीग में परीक्षा होगी। हरमनप्रीत सिंह की टीम भुवनेश्वर और राउरकेला में चार टीमों के साथ दो-दो बार टकराएगी। मेजबान का पहला मैच 10 फरवरी को स्पेन से होगा। हॉकी इंडिया ने गुरुवार को लीग के लिए 24 सदस्यीय टीम घोषित की। मिडफील्डर हार्दिक सिंह टीम के उपकप्तान होंगे। दस से होगी शुरुआत : भुवनेश्वर चरण 10 से 16 फरवरी तक जबकि राउरकेला चरण 19 से 25 फरवरी तक चलेगा। भारतीय टीम आयरलैंड, नीदरलैंड्स, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से दो-दो बार खेलेगी। श्रीजेश बनेंगे दीवार : भारतीय टीम में स्ट्राइकर बॉबी धामी और गोलकीपर पवन नहीं हैं। यह दोनों दक्षिण अफ्रीका

हमने सोच समझकर काफी संतुलित टीम चुनी है। इसमें अनुभवी और युवा खिलाड़ी दोनों हैं। हमारा लक्ष्य एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना है। शीर्ष टीमों के खिलाफ खुद को आंकने का अच्छा मौका है। -कैप फुल्टन, भारतीय कोच



दिल की बात | भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ने 13 महीने पहले हुई खोफनाक हादसे के बारे में खुलकर बात की, रजत कुमार और निशु कुमार का आभार जताया

ऋषभ पंत बोले, कार दुर्घटना के बाद मुझे पैर गंवाने का डर था

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ करीब 13 महीने पहले हुई खोफनाक दुर्घटना सबको याद होगी। वह अब उस हादसे से शारीरिक रूप से बेशक उबर चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनका खोफ अब भी उनकी बाताओं में उजर आता है। रुड़की जा रहे थे : उन्होंने उस दुर्घटना के बारे में कहा है कि उस हादसे के बाद उन्हें दानों पैर गंवाने का डर था। पंत दिसंबर 2022 में दिल्ली से अपने परिवार के पास अपने शहर रुड़की जा रहे थे जब उनकी कार सड़क के बीच डिवॉइडर से टकरा गई। वह उस समय मीरपुर टेस्ट में भारत की जीत में अहम भूमिका



निभाकर बांग्लादेश से लौटे थे। स्टार स्पोर्ट्स की सीरीज 'बिलीव : टू डैश एंड बैक' में खास बातचीत में भारतीय विकेटकीपर ने उस भयानक एक्सीडेंट को याद करते हुए कहा, उस दिन मुझे लगा कि दुनिया में मेरा टाइम पूरा हो गया है। खुलकर बात की : 26 साल के पंत ने पहली बार उस घटना पर

डॉक्टरों ने कहा कि दुर्घटना के बाद कोई फ्रेक्चर नहीं था। यह भयानक हादसा था और लोगों को बुरा लगता है कि यह मेरे साथ हुआ। मैं भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ? लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि हादसे के बाद भी मैं जीवित था। -ऋषभ पंत, भारतीय बल्लेबाज

खुलकर बात की है। हादसे को याद करते हुए उन्होंने कहा, अगर कोई नस थ्रॉटग्रस्त होती तो पैर गंवाने का डर था। मैं उस समय उबर गया था। मैंने एक्सव्यू ली थी लेकिन वह बाद में सैडान लग रही थी। रजत-निशु की वजह से जिंदा हूँ : दो व्यक्ति रजत कुमार और निशु कुमार ने पंत को उनकी एक्सव्यू से निकाला जो बाद में आग की लपटों में घिर गई थी। पंत ने कहा, मैं आज रजत और निशु की वजह से जिंदा हूँ। मैं आजीवन इन दोनों का आभारी रहूंगा। पंत ने कहा, जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हुआ। हादसे के समय चोट के बारे में तो पता था लेकिन मैं खुशकिस्मत था क्योंकि यह

दौर पर टीम में शामिल थे। गोलकीपर का जिम्मा दीवार कहे जाने वाले दिग्गज पी आर श्रीजेश के कंधों पर रहेगा। भविष्य के बारे में सोचने लगा : पंत बोले, जब से मैंने खेलना शुरू किया था, कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन इस चोट के बाद भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि चोट से उबरने में कितना समय लगेगा। इस पर उन्होंने बताया कि इसमें 16 से 18 महीने लग सकते हैं। तब मैंने कहा कि मैं उसमें से छह महीने घटा लूंगा। पंत का शुरुआती इलाज देहरादून में हुआ जिसके बाद उन्हें मुंबई ले जाया गया जहां बीसीसीआई ने उनका इलाज करवाया। ऑपरेशन के बाद पंत ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन शुरू किया।

खेल 30s

पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं जडेजा

विशाखापत्तनम। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को पैर की मांसपेशियों की चोट से उबरने में अधिक समय लगेगा। वह इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की टेस्ट सीरीज के बाकी मुकाबलों से भी बाहर हो सकते हैं। हैदराबाद में पहले टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में रन आउट होने के दौरान जडेजा की पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। शुरुआत में वह शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट से बाहर हुए थे। पैर की मांसपेशियों की चोट से उबरने में कम से कम चार हफ्ते लगते हैं। अब उनके पूरी सीरीज से बाहर होने की संभावना है। अंतिम टेस्ट 7 से 11 मार्च तक धर्मशाला में खेला जाएगा।

रणजी : बड़ौदा के खिलाफ प्रिंस की जगह इशांत

नई दिल्ली। अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा शुक्रवार से यहां पालम मैदान पर शुरू होने वाले पांचवें रणजी टॉपी ग्रुप टी मैच में बड़ौदा के खिलाफ दिल्ली की अंतिम एकदश में खेलने उतरेंगे। 100 से अधिक टेस्ट मैच खेल चुके इशांत दिल्ली के घरेलू मैच में खेलने को तैयार हैं और वह प्रिंस यादव की जगह उतरेंगे। पालम के एयर फोर्स मैदान की पिच सपाट है लेकिन दिल्ली की सर्दी और बारिश से हुई नमी से तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। धूप नहीं निकली तो पिच की नमी से इशांत के साथ नवदीप सैनी और हिमांशु चौहान को मदद मिलेगी। मोहाली में उत्तराखंड के खिलाफ पिछड़ने के बाद जीत से दिल्ली का मनोबल बढ़ा होगा।

मैथ्यू-कार्स ने भारत-ए को 192 पर समेटा

अहमदाबाद। भारतीय युवा विगेंड मैथ्यू पोर्ट्स (57/6) और ब्राइडन कार्स (52/4) की रिविंग नहीं झेल पाई। इनकी कहर बरपाती गेंदों के सामने भारत-ए की टीम तीसरे और अंतिम अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को 192 रन पर ढेर हो गई। जवाब में इंग्लैंड लायंस ने खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 98 रन बना लिए थे। एलेक्स लीस (48) और ओलिवर प्राइस (20) स्टंप के समय क्रीज पर थे। अभिमान्यु इश्वरन की टीम ने मैच की पहली ही गेंद पर कप्तान का विकेट गंवा दिया जो पोर्ट्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। देवदत्त पडिवकल (65) और सराश जैन (64) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए।



कोलंबो में एकमात्र टेस्ट की पूर्वसंख्या पर गुरुवार को श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिस्सिल्ला (बाएं) और अफगानिस्तान के कप्तान हशममुल्ला शाहीदी।

चेन्नई ओपन : नागल पुरुष एकल में चुनौती देंगे

चेन्नई। हाल में ग्रैंड स्लेम टूर्नामेंट में वरीय खिलाड़ी को पराजित करने वाले पहले भारतीय बने सुमित नागल चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर 100 टूर्नामेंट के पुरुष एकल में भारतीय चुनौती की अग्रिम उतरेंगे। रामकृष्ण रामनाथन और मुकुंद शशिकुमार पुरुष एकल में अन्य भारतीय खिलाड़ी होंगे जिन्हें मुख्य ड्रॉ में वाइल्डकार्ड दिया गया है। नागल (26 वर्ष) ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 31वें वरीय और विश्व रेटिंग में 27वें स्थान पर काबिज कजाखस्तान के एलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। रविवार से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में इटली के लुका नार्डी शीर्ष वरीय खिलाड़ी होंगे।

थाईलैंड मास्टर्स : मंजूनाथ से फिर हारे श्रीकांत

बैंकोंक। दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत फिर हमवतन मिथुन मंजूनाथ से पार नहीं जा सके। दुनिया के 24वें नंबर की श्रीकांत को गुरुवार को थाईलैंड मास्टर्स बेडमिंटन में 63वें नंबर के मंजूनाथ ने 21-9, 13-21, 21-17 से मात दी। यह मंजूनाथ की श्रीकांत पर दो मुकाबलों में लगातार दूसरी जीत है। क्वार्टर फाइनल में मंजूनाथ नीदरलैंड्स के मार्क कालजोव से भिड़ेगे। महिला एकल में अग्रिमता वालिहान ने चीनी ताइपेई की यू पौ पाइ को 21-12, 15-21, 21-17 से मा दी। मालविका बंसोड को स्थानीय खिलाड़ी बुसानन आंगबेरंगफान के हाथों 22-24, 7-21 से हार मिली।

मुंबई ओपन के लिए चार भारतीयों को वाइल्ड कार्ड

मुंबई। भारत की अकिंता रेना, सहजा यमलापल्ली और रूतुजा भोंसले की महिला टिकटों के अलावा महाराष्ट्र की युवा वैष्णवी अदकर को 5 से 11 फरवरी तक होने वाले डब्ल्यूटीए मुंबई ओपन टैनिंस के एकल मुख्य ड्रॉ के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। डब्ल्यूटीए 125 के सीरीज टूर्नामेंट में 18 वर्षीय आर्याना सबालका ने 2017 में खिताब जीता था। थाईलैंड की लुकसिका कुमखुम ने 2018 के अंतिम चरण में यह खिताब जीता था। क्वालीफाइंग दौर 3 और 4 फरवरी को खेले जाएंगे। मुख्य दौर के मुकाबले 5 फरवरी से शुरू होंगे।

सोशल मीडिया से

इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड में अपनी टीम में शामिल किया है। इस पर इंग्लैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया एक्सप्रेस पर उनकी तस्वीर के साथ संदेश दिया है। इसमें लिखा है कि अपना 184वां टेस्ट खेलने वाले 41 साल के एंडरसन लगातार 22वें साल टेस्ट खेल रहे हैं। वह दो ऐसे खिलाड़ियों के साथ मैदान पर नजर आएंगे जो उनके टेस्ट पदार्पण के समय पदा भी नहीं हुए थे।

जरा हटकर

मेसी-रोनाल्डो की टक्कर नहीं देख सके प्रशंसक

फुटबॉल के प्रशंसकों के लिए इससे ज्यादा मायूसी और क्या हो सकती है। जिस दिन का वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस दिन उनकी मुराद पूरी नहीं हो सकी। दिग्गज फुटबॉलर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी एक मैत्री मुकाबले में गुरुवार को मैदान पर एक-दूसरे से भिड़ने वाले थे। लेकिन चोट के कारण रोनाल्डो लियोनेल मेसी के खिलाफ बहुचर्चित नुमाइशी फुटबॉल मैच नहीं खेल सकेगे। रोनाल्डो के सऊदी अरब के क्लब अल नस्र और मेसी के अमेरिकी क्लब इंटर मियामी के बीच गुरुवार देर रात यहां मुकाबला होगा था। अल नस्र के कोच लुइस कास्ट्रो ने कहा, क्रिस्टियानो अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं। उम्मीद है कि वह आगले कुछ दिन में फिट हो जाएंगे। वह इंटर मियामी के खिलाफ नहीं खेल सकेगे। मेसी और रोनाल्डो की प्रतिद्वंद्विता स्पेन में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के लिए खेलने के दिनों से चली आ रही है। दोनों मिलकर पिछले 15 में से 13 बैलन डि'ऑर् पुरस्कार जीत चुके हैं।





कठिन दिनों की तकलीफें

- कमर व उन दिनों के दर्द • खून की कमी • कमजोरी • चिड़चिड़ापन
- थकान • हार्मोन्स की गड़बड़ी • खून साफ़ करे • रूप निखारे आदि में सहायक

90 वर्षों से महिलाओं की No.1 औषधि व टॉनिक



पूरे माह रहें एक्टिव, फिट व स्वस्थ

हेमपुष्पा

*Source: Brand Research Report, IBC 2019



बुसेल्स में किसानों का उग्र प्रदर्शन

बेल्जियम की राजधानी बुसेल्स में गुरुवार को यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया। बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देशों के किसानों ने यूरोपीय संसद का मार्ग टूटकर लगाकर अवरोध कर दिया। महंगाई, टैक्स आदि मुद्दों पर गुरसाए किसानों ने वहां आगजनी की, साथ ही पत्थर और अंडे भी फेंके। किसानों को पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने आसू गैस और पानी की बोझारें की।

तकनीक 30^s

व्हाट्सएप पर पूरे महीने की रिपोर्ट बन जाएगी

व्हाट्सएप एक नए ऑटोमेटिक अकाउंट रिपोर्ट फीचर पर काम कर रहा है। यह अपने आप किसी भी अकाउंट और चैनल की मंथली रिपोर्ट जनरेट करेगा। हालांकि, इसका उपयोग करने के लिए फीचर को इनबल करना होगा। इस फीचर को भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ लाया जा रहा है। वेबसाइट वेबिटाइफो ने इसके बारे में जानकारी दी है। यह फीचर अकाउंट और चैनल दोनों के लिए आ रहा है। सबसे पहले बीटा यूजर के लिए जारी किया जाएगा।

एप्पल ने विजनओएस 1.0.2 अपडेट जारी किया

एप्पल ने विजनओएस 1.0.2 जारी किया है। यह सॉफ्टवेयर विजन प्रो पर चलता है। इसमें सफारी और अन्य वेब एप्लिकेशन को पावर देने वाले ब्राउजर इंजन वेबकिट में भेद्यता को ठीक करना शामिल है। कंपनी के अनुसार, यदि बग का फायदा उठाया जाता है, तो यह दुर्भावनापूर्ण कोड को प्रभावित डिवाइस पर चलाने की अनुमति देता है। तकनीकी दिग्गज ने विजन प्रो हेडसेट के लिए अपना पहला सुरक्षा पैच जारी किया है, ताकि उस भेद्यता को ठीक किया जा सके।

गूगल बॉर्ड चलाने के लिए पैसे देने होंगे

अल्फाबेट ने जैमिनी अल्ट्रा आर्किटेक्चर द्वारा संचालित अपने अपकमिंग चैटबॉट, बॉर्ड एडवांस के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, जैमिनी अल्ट्रा के मूल में, हाईटेक एआई टूल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कोड सहित विभिन्न तौर-तरीकों में जटिल कार्य करने के लिए तैयार है। सुदूर पिछाई ने कहा, यह (बॉर्ड) अब जैमिनी प्रो द्वारा संचालित है। उम्मीद है कि यूजर को 10 से 20 डॉलर की रकम चुकानी पड़ सकती है।

क्रम संख्या	ई-नीलामी के आरम्भ होने की तिथि तथा समय	एस्सेट्स जिनकी नीलामी की जानी है
1.	02.02.2024 को 10:30 बजे	12191 (F1, F2 & R1), 12457 (F1, F2 & R1), 12572 (F1), 12918 (F1), 14041 (R1), 14316 (F1), 14507 (F1, F2 & R1), 15035 (F1 & R1), 15657 (F1), 19338 (F1), 20914 (F1), 20946 (F1), 20958 (F1), 22429 (F1), 22463 (F1), 22482 (F1)
2.	05.02.2024 को 10:30 बजे	22168 (F1), 20473 (F1), 20409 (F1, 14731 (F1), 20473 (R1), 22950 (F1), 15060 (F1), 12066 (F1), 12428 (F1), 14731 (R1), 22168 (F2), 15060 (R1), 22986 (F1), 13430 (F2), 20488 (F1)
3.	06.02.2024 को 10:30 बजे	12005 (F1), 12038 (F1), 12148 (R1), 12481 (F1, F2 & R1), 14714 (F1), 22421 (F1, F2 & R1), 22438 (F1)
4.	07.02.2024 को 10:30 बजे	01 LVPH (24 टन) राउंड ट्रिप पर प्रत्येक गाड़ी में - 12226/12225, 12236/12235, 12284/12283, 12425/12426, 12432/12431, 12442/12441, 12445/12446, 12488/12487, 14033/14034, 22412/22411, 22420/22419, 22428/22427, 22429/22430, 22434/22433, 22460/22459 तथा 01 VP (23 टन) राउंड ट्रिप पर गाड़ी संख्या : 22418/22417
5.	09.02.2024 को 10:30 बजे	12284 (F1), 14014 (F1), 14303 (F1 & R1), 14305 (F1 & R1), 14331 (F1, F2 & R1), 14545 (F1, F2 & R1), 22168 (R1), 22404 (F1), 22418 (F1), 22654 (F1)
6.	12.02.2024 को 10:30 बजे	12011 (F1), 12017 (F1), 12029 (F1), 12040 (F1), 12148 (F1 & F2), 12432 (F1), 12455 (F1), 14041 (F1), 14553 (F2), 15035 (F2), 22454 (F1, F2 & R1), 22461 (F1)
7.	13.02.2024 को 10:30 बजे	04304 (F1, F2 & R1), 12013 (F1), 12015 (F1), 12031 (F1), 12448 (F1), 12459 (F1), 12986 (F1), 22414 (F1), 22472 (F1, F2 & R1), 20502 (F1), 22806 (F1)
8.	14.02.2024 को 10:30 बजे	12045 (F1), 12265 (F), 12754 (F1), 14152 (F1), 14164 (F1), 14681 (F1), 20938 (F1 & R1), 22401 (F1)
9.	15.02.2024 को 10:30 बजे	12463 (F1), 12584 (F1), 14035 (F1, F2 & R1), 14212 (F1), 14521 (F1, F2 & R1), 14553 (R1)

महत्वपूर्ण सूचना: 1. ई-नीलामी के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को https://www.ireps.gov.in/html/helpdesk/learning_centre.html (e-Auction leasing section) पर जाने की सलाह दी जाती है। 2. धरोहर राशि जमा (ईएमडी): नीलामी के दौरान कुल संविदात्मक बोली मूल्य का 5% ऑनलाइन जमा किया जाना है। सफल बोलीदाता की ईएमडी सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाएगी। 3. रेलवे प्रशासन किसी भी समय इन निविदाओं / अनुबंधों को समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार रखता है या इनके संबंध में किसी संशोधन अथवा अतिरिक्त नियमों और शर्तों के साथ इन निविदाओं अथवा अनुबंधों के बीच में ही समाप्त करने अथवा जारी रखने के संबंध में जो की इन ट्रेनों के जारी रहने अथवा समाप्त होने कि स्थिति पर निर्भर करता है। 338/2024

चिंताजनक : बढ़ते तापमान के बीच सांस नहीं ले पा रहे पेड़-पौधे

अवशोषित होने की जगह वायुमंडल में वापस आ रहा कार्बन डाइऑक्साइड



- वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम होने से पर्यावरण पर असर होगा
- वैज्ञानिकों ने इसके पीछे मुख्य कारण उच्च तापमान और पानी की सप्लाई में कमी बताया

पुरानी लकड़ी पर शोध करेंगे वैज्ञानिक

अब वैज्ञानिक जीवाश्म का रूप ले चुके लकड़ी पर शोध करने की योजना बना रहे हैं ताकि दस हजार साल पहले फोटो-रेस्पिरेशन का दर पता लग सके। इनका कहना है कि लकड़ी में मौजूद कुछ आइसोटोप विशेषकर मैथेयिलसल समूहों से इसका पता लगेगा। अध्ययन के मुख्य लेखक और पेन स्टेट के जियोसाइंस के रिसर्च प्रोफेसर मैक्स लॉयड ने कहा, 'वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित करने के बजाए वापस भेज रहे हैं। इस प्रक्रिया को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं जो सामान्य नहीं है।'

कार्बन को अवशोषित करने में सफल नहीं

सामान्यतया प्रकाश संश्लेषण के जरिए पेड़ हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। यह उनकी वृद्धि में सहायक होता है। हालांकि उच्च तापमान और सीमित पानी की सप्लाई से यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में चल रही है, जिसमें पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं, इसे 'फोटो-रेस्पिरेशन' नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार फोटो-रेस्पिरेशन की दर दोगुनी हो गई है, जिसके पीछे गर्म जलवायु और पानी की कमी मुख्य कारण हैं। ऐसी प्रतिक्रिया दिन के तापमान में की बढ़तीरती होने के बाद होती है।

सर्दियों में बढ़ जाता है बालों का झड़ना और रूसी असरदार उपाय के लिए चुनें केवल एक्सपर्ट



बाल झड़ना रोके। नए बाल उगाए

सर्दियों में ठंड बालों की प्राकृतिक नमी छीन लेती है, जिससे बाल रूखे एवं कमजोर होकर झड़ने लगते हैं और रूसी की समस्या भी बालों को घेर लेती है। ऐसे में आपके बालों को खास जरूरत है केश किंग-भारत के नं. 1 हेयरफॉल एक्सपर्ट की।

क्लिनिकल टेस्ट ने प्रमाणित किया है कि 21जड़ी-बूटियों वाला केश किंग आयुर्वेदिक तेल न केवल बालों का झड़ना रोके, साथ ही नए बाल उगाने में भी मदद करे।

"तो अब सर्दियों में हेयरफॉल नहीं, पाएं सेहत से भरे सुन्दर बाल।"

I trust only Kesh King Oil & Shampoo

International Certificate

Very effective in decreasing hairfall and encouraging hair re-growth.

21 AYURVEDIC HERBS

Kesh King AYURVEDIC OIL

Kesh King AYURVEDIC HAIRFALL EXPERT SHAMPOO

India's No.1

emami Kesh King

INDIA'S No.1 HAIR FALL EXPERT

तेल ₹49/- onwards

शेम्पू ₹65/- onwards

₹49/- (सभी कर सहित) 30ml के लिए. *₹65/- (सभी कर सहित) 80ml के लिए. #अगस्त 2018 में आयोजित किए क्लिनिकल अध्ययन के परिणामों के आधार पर. स्रोत: आयुर्वेदिक तेल पर केंद्रित वर्ल्ड पैनेल के आंकड़े, अप्रैल 2020 से मार्च 2022.

Stylish Design Superior Performance

KUTCHINA THE KITCHEN EXPERTS

UP TO 25% OFF

OMEGA DLX 500 (MIXER GRINDER)

PLUTO DLX (INFRARED COOKER)

APOLLO 500 (JUICER MIXER GRINDER)

ZEPHIRE 9 L (OTC)

OMEGA DLX 500 (MIXER GRINDER)

MAGMA EXCEL (INFRARED COOKER)

FABIO (COOKTOP)

MAGNETO (INDUCTION COOKER)

VIENA 500 (INDUCTION COOKER)

ENDURA (NON-STICK COOKWARE)

MODULAR KITCHEN | KITCHEN APPLIANCES | WATER HEALTHIFIERS | MODULAR WARDROBES | SMALL APPLIANCES

Toll free: 1800 4197 333 | www.kutchina.com | follow us on @kutchinaconnectofficial

AUTHORISED DISTRIBUTOR: West Delhi - Ersheen Enterprises-9953785583
 South Delhi - B.L Enterprises-9811385888 North Delhi - Shyama Trading Co.-9313317228
 Noida - Gouri Trading Company-7838075706 Ghaziabad Trans Hindon - ASR
 Lights-9350316555 Faridabad - Super Products-9810931777 Gurgaon City - Shri
 Siddhivinayak Enterprises-9599333313 Gurugram Outer - Dinesh electrical-9891920053

STATE TRADE ENQUIRY CONTACT NO-7827737677

Find us at: amazon, Flipkart, croma, Reliance Digital, spencers